



सेमीकॉन इंडिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी

ब्रिक्स घोषणापत्र भारत पर भरोसे का प्रमाण

नई दिल्ली। अपने 76वें जन्मदिन के अवसर पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती वैश्विक साख, आर्थिक मजबूती और तकनीकी प्रगति का एक मजबूत खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाया जाना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि वैश्विक मंच पर भारत के प्रति दुनिया का भरोसा किस तेजी से बढ़ रहा है।

नई दिल्ली में हुए 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भू-राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने के मकसद से रात भर चली बातचीत के बाद भारत ने नई दिल्ली घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाने में सफलता हासिल की।

भारत के आर्थिक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की तिमाही जीडीपी रिपोर्ट सितंबर में जारी की गई थी और मुश्किल दौर के बावजूद भारत ने 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की तिमाही जीडीपी रिपोर्ट सितंबर में ही जारी की गई थी, और इस मुश्किल



दौर में भी भारत ने 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। उन्होंने यह भी कहा कि जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसी दौरान भारत की सांख्यिक रेटिंग को अपग्रेड किया, जिसे उन्होंने लगभग तीन दशक या करीब 35 साल बाद हुई एक महत्वपूर्ण घटना बताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। दूसरी तरफ, भारत में दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को भारत में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय भरोसे का एक और उदाहरण बताया। नई दिल्ली में भारत द्वारा इस समूह की मेजबानी के बाद यह शिखर सम्मेलन तीन दिन पहले संपन्न हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर में हुई अन्य घटनाओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इसी सितंबर महीने में, ठीक 10 दिन पहले, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित हुआ था। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्रॉटम टेक्नोलॉजी के ज़रिए समावेशी वित्त पर चर्चा हुई।

उन्होंने आगे कहा कि इसी दौरान भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 3,000 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह से चालू हो गया। भारत की आर्थिक वृद्धि को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इसी समय-सीमा में, सितंबर में ही, भारत की तिमाही जीडीपी रिपोर्ट जारी की गई थी। इस मुश्किल दौर में भी भारत ने 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की और उसे प्रदर्शित किया।

हिंदी भाषा विवाद पर विजय सरकार को लगाई फटकार

नवोदय विद्यालय पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

चेन्नई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य के हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन चिन्हित करने के अपने दिसंबर 2025 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग जरूरी है। अदालत ने सवाल किया कि अगर समवर्ती सूची में केंद्र सरकार कोई नीति लेकर लाती है और हर राज्य यह कहने लगे कि वह उसे स्वीकार नहीं करता, तो संघीय व्यवस्था कैसे चलेगी। पीठ ने तमिलनाडु सरकार से इस मामले में अपना नजरिया बदलने को भी कहा।

15 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य के प्रत्येक जिले में नवोदय



विद्यालय स्थापित करने के लिए जरूरी जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया था।

गुरुवार को तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने बताया कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया है। इस पर पीठ ने स्पष्ट किया कि वह 15 दिसंबर 2025 के आदेश को वापस नहीं ले रही है। हालांकि, अदालत ने अब राज्य सरकार को जमीन चिन्हित

करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है। यह निर्देश राज्य की विशेष अनुमति याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नवोदय विद्यालय स्थापित करने का विरोध मुख्य रूप से इन स्कूलों में लागू तीन-भाषा नीति वाले पाठ्यक्रम को लेकर किया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य के वकील से कहा कि यदि राज्य यह कहता है कि वह तमिलनाडु की जमीन पर हिंदी पढ़ाए जाने के कारण नवोदय विद्यालय नहीं चाहता, तो पहले अपना नजरिया बदलना होगा। इस पर जयदीप गुप्ता ने कहा कि तमिलनाडु सरकार हिंदी की पढ़ाई का बिल्कुल विरोध नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल पहले से मौजूद हैं, जहां हिंदी पढ़ाई जाती है।

बालाघाट में बच्चों की मौतों पर राहुल ने उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 17 सितंबर को बालाघाट में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत की खबरों के बाद मध्य प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने इन मौतों के लिए राज्य में बीमारी, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और साफ पानी न मिल पाने को जिम्मेदार ठहराया। झू पर एक पोस्ट में, गांधी ने राज्य सरकार की धीमी प्रतिक्रिया और असंवेदनशीलता की निंदा करते हुए कहा कि बालाघाट में बीमारी, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत हो गई है। संवेदनहीनता का आलम यह है कि मासूम जानें जाती रहीं, फिर भी प्रतिक्रिया धीमी रही और सरकार सोती रही।

उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से कहा कि



मुख्यमंत्री जी, अगर आपको दीये जलाने और त्योहार मनाने के बाद समय मिले, तो ज़रा राज्य की जमीनी हकीकत पर भी नज़र डालिए। गांधी ने सरकार पर चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, बीमारियों को रोकने में नाकामी, कुपोषण, और मिलावटी दवाओं व अवैध शराब जैसी समस्याओं का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह मध्य प्रदेश भर में छात्रों, युवाओं और आम जनता से फ़ीडबैक लेने के लिए इंदौर जा रहे हैं। उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की भी आलोचना करते हुए कहा

प्रधानमंत्री के जीवन पर मुख्यमंत्री ने लिखा आलेख

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने आलेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा को सेवा, सुशासन, अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ते हुए गुजरात के पुनर्निर्माण से लेकर विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य तक की यात्रा का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की अवधारणा गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और जनजातीय समाज की आकांक्षाओं से जुड़ी है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के आलेख को साझा करते हुए छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और विशेष रूप से बस्तर में आए परिवर्तन को रेखांकित किया है। कार्यालय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा इस बात का बड़ा उदाहरण है।



मुख्यमंत्री ने किया ‘आशीर्वाद का दीया’ प्रज्वलित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर अपने निवास पर ‘आशीर्वाद का दीया’ प्रज्वलित कर उनके स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की मंगलकामना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के प्रति समर्पण को स्मरण करते हुए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित किए हैं। गरीब कल्याण से लेकर सुशासन, अंत्योदय से लेकर आत्मनिर्भर भारत और विरासत के सम्मान से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक उनकी यह यात्रा देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

राहुल को प्रधानमंत्री मोदी पर बोलने का नैतिक हक नहीं

बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि गांधी को ऐसा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बोम्मई ने 17 सितंबर को गुदग में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं। बोम्मई ने विपक्षी नेताओं पर मोदी सरकार के तहत भारत की आर्थिक प्रगति को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत की मौजूदा 7.8 प्रतिशत की विकास दर का जिक्र करते हुए इसे शानदार प्रगति बताया। बोम्मई ने कहा कि ट्रंप जो चाहें वो करते हैं, लेकिन राहुल इसे हमारे देश की स्थिति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जोरो है, तो उन्हें खुशी हुई थी, लेकिन आज भारत 7.8% की विकास दर हासिल कर रहा है – यह एक ऐसी शानदार प्रगति है जो न तो अमेरिका के पास है और न ही रूस के पास।



पंजाब में दोबारा चुनकर आएगी भगवंत मान सरकार: सिसोदिया

नई दिल्ली। आप नेता मनीष सिसोदिया ने 17 सितंबर को कहा कि पंजाब के लोग भगवंत मान सरकार के कामकाज से खुश हैं और उसे दोबारा चुनना चाहते हैं, जबकि गोवा और गुजरात के वोटर बदलाव चाहते हैं। आप की दोबारा गठित पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (पीएसी) की पहली बैठक के बाद बोलते हुए, सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर बनाया गया है और कमिटी में नए सदस्य शामिल हुए हैं। सिसोदिया ने कहा कि आप की पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर नियुक्त किया गया और नए सदस्य शामिल किए गए। इस नई पीएसी की पहली बैठक में चर्चा की शुरुआत राजस्थान के बारों में मिली अप्रत्याशित जीत और वहां के लोगों द्वारा भाजपा की नीतियों को नकारे जाने से हुई—जिससे यह उम्मीद जगी है कि भाजपा का एक मजबूत विकल्प उभर रहा है।



पीएम मोदी के जन्मदिन पर राहुल समेत कई दिग्गजों ने दी बधाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 76 साल के हो गए। सभी पार्टियों के नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, वहीं कुछ लोगों ने इस मौके पर उनकी सरकार और राजनीतिक कामकाज पर अपनी राय भी रखी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपना संदेश संक्षिप्त रखा। गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। मुख्यमंत्री विजय ने एक्स पर लिखा कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री थिरु नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ, जो एक मजबूत भारत बनाने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं। मैं दिल से आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी और कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।



राहुल गांधी के इंदौर इवेंट पर नया विवाद

नई दिल्ली। कांग्रेस ने 19 सितंबर को यहां अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए सरकारी मैदान के अस्थायी लीज के तौर पर 10.08 लाख रुपये जमा किए थे, जिसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने पार्टी से लगभग 4 लाख रुपये और जमा करने को कहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कमर्शियल और एजुकेशनल हब, इंदौर में स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम के पांचवें एडिशन को संबोधित करेंगे। आईडीए राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ऑर्गनाईटी की ओर से इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को जारी एक लेटर में कहा गया है कि 17 से 19 सितंबर तक होने वाले छात्रों की गूंज इवेंट के लिए 12,000 वर्ग मीटर जमीन अस्थायी लीज पर दी गई थी, लेकिन साइट के निरीक्षण से पता चला कि पार्टी ने 14 सितंबर से ही इस प्लॉट के 4,800 वर्ग मीटर हिस्से का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके बदले में, आईडीए ने कांग्रेस से तीन दिनों की लीज फीस के तौर पर अतिरिक्त 4.03 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है।



यूपीआई टैक्स पर सरकार के दावों को कांग्रेस ने नकारा

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति में शामिल उसके सांसदों ने ज्यादा कीमत वाले यूपीआई पेमेंट पर फीस लगाने के फ़ैसले का समर्थन किया था। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार यूपीआई टैक्स के फ़ैसले के बाद हुए जबरदस्त विरोध से ध्यान भटकाने की बेहद घटिया कोशिशें कर रही है। सरकार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने व्यापारियों को 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर फीस लगाने के फ़ैसले की आलोचना की थी। सरकार का कहना था कि एक संसदीय स्थायी समिति ने इस कदम का समर्थन किया था और समिति में शामिल कांग्रेस सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया था। इसके बाद विपक्षी पार्टी का यह बयान आया। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने यूपीआई के लिए अलग-अलग स्तरों वाले मर्चेड डिस्काउंट रेट (एमडीआर) या रेवेन्यू फ्रेमवर्क की मांग की है और कहा है कि इसे बिना किसी देरी के नोटिफाई और लागू किया जाना चाहिए। बीजेपी पदाधिकारी ने बताया कि 12 अगस्त को जब रिपोर्ट को मंजूरी दी गई।

सेवा संकल्प अभियान

पीएम नरेंद्र मोदी का जीवन जनसेवा और राष्ट्र निर्माण को समर्पित : अरुण साव

बिलासपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत आज बिलासपुर जिले में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउंड में उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। यहां एक साथ 1 लाख 25 हजार दीप प्रज्वलित किए गए। लगभग शाम 7 बजे जिलेभर में एक साथ लगभग 10 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। शहर से लेकर गांवों तक दीपों की रोशनी से बिलासपुर जगमगा उठा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने उत्साह के साथ दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद का दीया अभियान में सहभागिता निभाई। सेवा, समर्पण, सुशासन और

जनभागीदारी की भावना से आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया। दीपों की रोशनी से पुलिस परेड ग्राउंड का पूरा परिसर जगमगा उठा। कार्यक्रम में बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, नगर निगम महापौर श्रीमती पूजा विधानी, क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सक्ती, नगर निगम सभापति श्री विनोद सोनी, संभागायुक्त श्री सुनील जैन, सीसीएफ श्री मनोज पांडे, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री चंद्रप्रकाश वाजपेयी, श्री दीपक सिंह, श्रीमती हर्षिता पाण्डेय, श्री किशोर राय, श्रीमती वाणी राव सहित जनप्रतिनिधि,



अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होकर दीप प्रज्वलित किये। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

मोदी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन जनसेवा के प्रति समर्पण की यात्रा है। वे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बिलासपुर ने इतिहास रचा है और पुलिस परेड ग्राउंड इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बना है। श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब परिवारों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों को इनका लाभ मिला है। महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के

विकास को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से प्रधानमंत्री के संवाद तथा उनके उत्साहवर्धन का भी उल्लेख किया। श्री साव ने कहा कि जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के इस संकल्प को आगे बढ़ाने में समाज की सहभागिता महत्वपूर्ण है। ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम इसी सामूहिक सहभागिता और सेवा भावना का प्रतीक है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ के माध्यम से लाखों लोगों ने अपने स्नेह और शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने आवास, स्वास्थ्य सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों का उल्लेख किया।

आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का नवजागरण

विष्णु देव साय सरकार ने गढ़ी छत्तीसगढ़ की नई पहचान

विरासत से विकास तक : जब संस्कृति बनी सुशासन की आधारशिला

शक्तिपीठों के विकास, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, लोककलाओं के संरक्षण,
संत परंपराओं का सम्मान और यात्रा सुविधाओं के विस्तार से छत्तीसगढ़ की
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को मिली नई ऊर्जा

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



शक्तिपीठ परियोजना आस्था को जोड़ने वाला 1000 किलोमीटर का सर्किट



माँ दत्तेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ महामाया, माँ बागेश्वरी और माँ चंद्रहासिनी जैसे प्रमुख शक्तिस्थलों को जोड़ते हुए लगभग 1000 किलोमीटर का आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना श्रद्धा, संस्कृति और विकास का सुंदर संगम बनेगी।



मंदिरों का जीर्णोद्धार सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन



प्रदेशभर में प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। इससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है।



श्री रामलला दर्शन योजना श्रद्धालुओं को आस्था से जोड़ने का सेतु



अब तक लगभग 42 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन कर चुके हैं, जबकि 5 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिक देश के विभिन्न तीर्थस्थलों का लाभ ले चुके हैं। यह योजना आस्था और जनसेवा का प्रभावी माध्यम है।

महाकुंभ 2025 में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक सहभागिता



प्रयागराज में 4.5 एकड़ में बना छत्तीसगढ़ पैवेलियन 45 दिनों तक आस्था, संस्कृति और सेवा का केंद्र रहा। 50 हजार श्रद्धालुओं ने निःशुल्क आवास व भोजन की सुविधा का लाभ उठाया। राज्य की संस्कृति और पर्यटन की प्रदर्शनी ने देश-विदेश के आगंतुकों को आकर्षित किया।



“छत्तीसगढ़ प्रभु श्रीराम का ननिहाल, माता कौशल्या की जन्मभूमि और संत परंपराओं की पावन धरती है। हमारी सरकार आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शक्तिपीठ परियोजना, रामलला दर्शन योजना, मंदिरों के जीर्णोद्धार, लोक कलाकारों के प्रोत्साहन और धार्मिक पर्यटन के विकास के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा दे रहे हैं। हमारा विश्वास है कि कला समाज की आत्मा है और आस्था हमारी सबसे बड़ी शक्ति। विरासत के संरक्षण और जनसेवा के माध्यम से हम नए, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं।”

-विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



चिन्हारी योजना लोक संस्कृति संरक्षण का सशक्त माध्यम



लोक कलाकारों, शिल्पकारों, गायकों और नर्तकों का पंजीयन कर व्यापक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। चयनित कलाकारों को आर्थिक सहायता, मंचों पर प्रस्तुति के अवसर और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नई पीढ़ी को लोक संस्कृति से जोड़ा जा रहा है।



मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 कलाकारों को सम्मान व संबल



लोकनृत्य, लोकगायन, लोकनाट्य, वाद्ययंत्र, शिल्पकला, पारंपरिक पाककला सहित विभिन्न विधाओं के कलाकारों को प्रतिवर्ष 12 हजार से 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।



कर्मचारियों के लिए विपश्यना अवकाश अनूठी पहल की शुरुआत



शासकीय कर्मचारियों में मानसिक तनाव दूर करने और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विपश्यना (ध्यान) शिविरों में जाने के लिए विशेष सवेतन अवकाश की अनूठी पहल शुरू की गई है।



संत परंपरा और आध्यात्मिक विरासत को नया सम्मान कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा को मिली नई पहचान



दामाखेड़ा का नाम अब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा घोषित किया गया है। प्रदेश के विभिन्न संत परंपरा केंद्रों और धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए योजनाबद्ध कार्य जारी है।



भोरमदेव से कौशल्या धाम तक धार्मिक पर्यटन का विस्तार



भोरमदेव सर्किट से स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 148 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। माता कौशल्या मंदिर, शिवरीनारायण, दंडकारण्य क्षेत्र सहित अन्य स्थलों का विकास कर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जा रहा है।



गौ संवर्धन और धार्मिक संरक्षण सामाजिक समरसता की दिशा में कदम



गौधाम योजना के माध्यम से गौधामों में आवश्यक सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

नया छत्तीसगढ़: विकास और विरासत का संतुलित मॉडल



आस्था, संस्कृति, पर्यटन और विकास के समन्वय से छत्तीसगढ़ अपनी हजारों वर्षों पुरानी विरासत को सहेजते हुए एक समृद्ध, सुरक्षित और सांस्कृतिक रूप से सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत नहीं लिख रहा, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी भविष्य की मजबूत नींव भी तैयार कर रहा है।

मुख्य
उपलब्धियाँ



शक्तिपीठ सर्किट से
आध्यात्मिक पर्यटन
को नई शक्ति



हजारों श्रद्धालुओं
को तीर्थयात्रा
की सुविधाएँ



लोक कलाकारों
का सशक्तीकरण
और सम्मान



युवाओं को छात्रवृत्ति
से उज्ज्वल भविष्य



धार्मिक धरोहरों का
संरक्षण और संवर्धन

आस्था हमारी पहचान, संस्कृति हमारी शान, सेवा हमारा संकल्प

सत्ता में आने के पहले क्या थे मोदी और संघ से कैसे जुड़े?

रिया दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 76वां जन्मदिन मनाया। इस बार जन्मदिन के साथ उनके राजनीतिक सफर का एक अहम पड़ाव भी जुड़ा है। 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद 2026 में सत्ता के शीर्ष पर उनके 25 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी के सत्ता में 25 साल पूरे होने की इस कहानी को समझने के लिए कई दशक पीछे जाना होगा। 1955 में नरेंद्र मोदी ने वडनगर प्राथमिक कुमार शाला में पढ़ाई शुरू की। 1957 के आसपास स्कूल के बाद वे अपने पिता की चाय की दुकान पर मदद करने लगे। 1962 में भारत-चीन युद्ध ने उनके मन पर असर डाला। उन्होंने जामनगर के सैनिक स्कूल बालाचट्टी में दाखिले के लिए आवेदन किया। हालांकि, वे दाखिला नहीं ले सके। कहा जाता है कि करीब 12 साल की उम्र में उन्होंने गांधीवादी नेताओं के साथ गोरक्षा को लेकर पहला उपवास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी वेबसाइट नरेंद्र मोदी डॉट इन के मुताबिक 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे मेहसाणा रेलवे स्टेशन पर सीमा की ओर जाने और वहां से लौटने वाले सैनिकों को चाय पिलाते थे। 1967 में बीएन हाई स्कूल, वडनगर से पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब 17 साल की उम्र में युवा नरेंद्र ने घर छोड़ दिया। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक यात्रा करना था। इस दौरान उनकी मुलाकात एकनाथ रानाडे से हुई। रानाडे से मुलाकात के बाद वे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए चंदा जुटाने के अभियान से जुड़े। इस अभियान में लोगों से एक-एक रुपये का सहयोग लिया जाता था। 1968 में वे बेलूर मठ पहुंचे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन वहाँ विश्वविद्यालय की डिग्री की आवश्यकता बताई गई। इसके बाद वे सिलीगुड़ी और गुवाहाटी होते हुए अल्मोड़ा के अद्वैत आश्रम पहुंचे। वहां भी उन्हें पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी गई। उन्होंने गरुड़ छट्टी की गुफाओं में ध्यान किया और कड़ाके की ठंड में समय बिताया। एक तूफान के दौरान उन्होंने बचाव कार्य में भी हिस्सा लिया। 1969 में उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग इलाकों की संस्कृति और जीवन को करीब से देखा। नदियों को मां मानने की परंपरा और अलग-अलग क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव ने उनका ध्यान खींचा। उनकी यात्रा राजकोट के रामकृष्ण मिशन पहुंचकर आगे बढ़ी। यहां स्वामी आत्मस्थानंद ने उन्हें कॉलेज की डिग्री हासिल करने और संन्यास लेकर दुनिया से अलग होने के बजाय सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ने की सलाह दी। करीब 18 महीने की आध्यात्मिक यात्रा के बाद 1970 में वे वडनगर लौटे। वहां सिर्फ एक दिन रुकने के बाद अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में उन्होंने गीतामंदिर बस स्टैंड के पास अपने चाचा बाबूभाई की चाय की दुकान पर काम किया। पास ही राष्ट्रीय सेवा संघ का डॉ. हेडगेवार भवन था। वहां उनकी पुराने परिचितों और आरएसएस कार्यकर्ताओं से दोबारा मुलाकात हुई। इसके बाद वे संगठन के काम में सक्रिय होते गए। सेवा और कर्मयोग की दिशा में उन्होंने संगठनात्मक जीवन को आगे बढ़ाया। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान वे दिल्ली पहुंचे। वहां 10 हजार से ज्यादा जनसंघ कार्यकर्ताओं के साथ गण सत्याग्रह में शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में बांग्लादेश को मान्यता देने की मांग की गई थी। नरेंद्र मोदी गिरफ्तार हुए और उन्हें कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया। 1972 में उन्होंने आरएसएस से जुड़कर संगठन के लिए काम करने का फैसला किया। प्रचारक के रूप में उनकी दिनचर्या सुबह करीब पांच बजे शुरू होती और देर रात तक संगठन का काम चलता था।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

3-यज्ञ-प्रक्रिया के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र का विकास

गतांक से आगे...

यद्यपि भारतीय दर्शन सम्बन्धी अनुसंधान करने वालों का ध्यान इस ओर नहीं गया, परन्तु यह प्रतीत होता है कि न्याय और वैशेषिक शास्त्र का उर्गम यज्ञ–प्रक्रिया सम्बन्धी मीमांसा के क्षेत्र में हुआ था।

आगे चल कर न्याय और वैशेषिक शास्त्र के इतिहास की विवेचना करते हुए यह दिखाया जायगा कि न्याय और वैशेषिक दोनों शास्त्रों का यद्यपि ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं, तो भी उन दोनों शास्त्रों का पूर्व मीमांसा से एक प्रकार का ऐतिहासिक सम्बन्ध है और साथ ही विचार–सम्बन्धी आन्तरिक सम्बन्ध भी है।

वैदिक दर्शनों में पूर्ण–रूप से बाह्यार्थवादी पूर्व–मीमांसा, न्याय और वैशेषिक ये तीन ही दर्शन हैं, आगे चलकर यह दिखाया, जायगा कि मीमांसा और न्याय दोनों ने ही वैशेषिक की बाह्य जगत् सम्बन्धी द्रव्य, गुण, कर्मादि पदार्थों की कल्पना और

कारणवाद को बहुत अंश तक अपनाया।

4–बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद

ऊपर भारतीय दर्शन की दो धाराओं का उल्लेख किया गया है।

एक, उपनिषदों का ब्रह्मवाद या आत्मवाद और दूसरी, बाह्य जगत् के यथार्थ स्वरूप को स्थापित करने वाली वैशेषिक की दार्शनिक प्रक्रिया, जिसको पूर्वमीमांसा एवं न्याय ने भी स्वीकार किया और जिसका उपनिषदों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इन दोनों धाराओं से न केवल भिन्न प्रत्युत उनसे सर्वथा विपरीत एक दार्शनिक धारा बौद्धों की है, जिसका मूल तत्त्व अनात्मवाद है।

वह अनात्मवाद जितना विरोधी उपनिषदों के आत्मवाद का है, उतना ही विरोधी वैशेषिक के द्रव्यवाद का भी है। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का आधारभूत सिद्धान्त है।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

वडनगर से वैश्विक मंच तक मोदी की राजनीतिक यात्रा

डॉ. ब्रह्मानंद राजपूत

17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 76वां जन्मदिन मनाया। गुजरात के छोटे से शहर वडनगर से शुरू हुई उनकी जीवन–यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता, गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने तक पहुंची। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा और विश्लेषण का विषय रहा है। उनके समर्थक उन्हें निर्णायक नेतृत्व, विकास योजनाओं और भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने वाला नेता मानते हैं, जबकि आलोचक आर्थिक नीतियों, रोजगार और सामाजिक मुद्दों को लेकर सवाल भी उठाते रहे हैं।

नरेंद्र दामोदरदास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ। उनका बचपन एक सामान्य परिवार में बीता। युवावस्था में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्राएं कीं और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वर्ष 1972 में वे संघ के प्रचारक बने। आपातकाल के दौर में भी वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। संगठन के प्रति उनकी कार्यशैली, अनुशासन और व्यापक संपर्क क्षमता ने उन्हें धीरे–धीरे भाजपा के संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक पहुंचाया। 1987 में वे भाजपा की गुजरात इकाई में संगठन की भूमिका से जुड़े और 1990 के दशक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में भी उनकी भूमिका बढ़ती गई। 1998 में वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बने। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला और मई 2014 तक इस पद पर रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में औद्योगिक निवेश, सड़क, बिजली, सिंचाई, शहरी विकास और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया। वर्ष 2003 में गुजरात में ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर बड़े निवेश और व्यापार सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ। गुजरात मॉडल को लेकर जहां समर्थकों ने आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों को रेखांकित किया, वहीं आलोचकों ने विकास के लाभों के समान वितरण और सामाजिक मुद्दों पर भी सवाल उठाए।

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और 26 मई 2014 को नरेंद्र



मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 2019 में भाजपा ने अपना प्रदर्शन और मजबूत करते हुए 303 सीटें जीतीं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ और नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की एक प्रमुख पहचान बड़े पैमाने पर लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाएं, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे का विस्तार रही है। प्रधानमंत्री जन–धन योजना ने बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में भूमिका निभाई। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता और शौचालय निर्माण को राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने आवास, कृषि सहायता, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे क्षेत्रों की नीति के केंद्र में रखा। इसी दौर में डिजिटल भुगतान और आधार आधारित सेवाओं का विस्तार भी तेजी से हुआ। यूपीआई ने डिजिटल लेन–देन को आम नागरिकों की रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए विनिर्माण, उद्योगिता, कौशल और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। दूसरी ओर, इन नीतियों के प्रभाव को लेकर रोजगार, छोटे कारोबार, ग्रामीण आय और आर्थिक असमानता जैसे सवाल भी सार्वजनिक बहस में बने रहे। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार के आर्थिक और कल्याणकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन केवल योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक और दीर्घकालिक प्रभाव से किया जाना चाहिए। इतिहासकितारें खोजें

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी मोदी सरकार के वर्षों में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार पर विशेष जोर रहा। इन परियोजनाओं ने संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। साथ ही, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश की उपयोगिता, उसके क्षेत्रीय वितरण और उससे रोजगार सृजन जैसे प्रश्न भी नीति–विश्लेषण का हिस्सा बने हुए हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर मोदी सरकार के दौरान भारत की सक्रियता और वैश्विक प्रभाव दोनों बढ़े। जी–20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत हुई, वहीं रूस–यूक्रेन युद्ध से लेकर ईरान–इजरायल संघर्ष और अमेरिका के साथ बदलते संबंधों के बीच भारत ने रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौरान तेल

और गैस की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए ऊर्जा सुरक्षा को भी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में रखा गया। दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति और अमेरिकी टैरिफ ने भारत के सामने आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती खड़ी की, जिसके बीच भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत और वैकल्पिक आर्थिक साझेदारियों पर जोर दिया। इस तरह मोदी सरकार की विदेश नीति में कूटनीति के साथ ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हित और बदलती वैश्विक शक्ति–समीकरणों के बीच संतुलन प्रमुख तत्व बनकर उभरे। सरकारीएजेंसियां खोजें

नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें संगठन से लेकर सरकार के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की एक लंबी प्रक्रिया दिखाई देती है। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर 2014 में देश के प्रधानमंत्री और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक उन्होंने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उनके कार्यकाल में जनधन, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आवास, किसान सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा, जल जीवन मिशन और डिजिटल भुगतान जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। साथ ही आर्थिक विकास, रोजगार, महंगाई, सामाजिक समावेशन और नीतियों के प्रभाव को लेकर बहस भी जारी है। अंततः, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा को केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों या सत्ता की राजनीति के संदर्भ में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह यात्रा बदलते भारत की राजनीतिक चेतना, शासन–व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में आए व्यापक बदलावों की भी कहानी है। वडनगर से शुरू हुआ यह सफर आज भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर वैश्विक कूटनीति तक अपनी छाप छोड़ चुका है। उनके लंबे सार्वजनिक जीवन ने भारतीय राजनीति और शासन की दिशा को प्रभावित किया है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का मूल्यांकन केवल उनके कार्यकाल की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से भी होगा कि उन्होंने भारत की राजनीति, शासन और वैश्विक भूमिका को किस हद तक नई दिशा दी। इतिहास के पन्नों में उनकी विरासत इस सवाल के साथ दर्ज होगी कि उनके नेतृत्व में बदला भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली आधार तैयार कर सका।

लवणासुर और शिव का त्रिशूल, श्रीराम की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने कैसे किया वध?

आशुतोष गर्ग

प्राचीन समय में मधु दैत्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे एक दिव्य त्रिशूल प्राप्त कर लिया। मधु चाहता था कि वह त्रिशूल सदैव उसके वंश में रहे, परंतु महादेव ने मधु से कहा, ‘तुम्हारे एक पुत्र के पास यह शूल रहेगा और जब तक उसके पास शूल होगा, वह अवध्य रहेगा।’ बाद में मधु ने वह शूल अपने पुत्र लवणासुर को सौंप दिया और स्वयं समुद्र के भीतर रहने लगा। लवणासुर बहुत क्रूर था। शिवजी के त्रिशूल के चलते कोई उसे मार नहीं पाता था। इस कारण वह निरंकुश और अत्याचारी हो गया।

लवणासुर के आतंक से दुखी होकर ऋषि–मुनि, श्रीराम के पास सहायता मांगने पहुंचे, तो उनकी व्य्था सुनकर श्रीराम के छोटे भाई भरत ने लवणासुर को मारने का

संकल्प किया। तभी शत्रुघ्न बोले, ‘श्रीराम के वनवास के दौरान भैया भरत ने नंदीग्राम में अनेक कष्ट उठाए हैं। इसलिए यह कार्य मुझे करने दीजिए।’

श्रीराम ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति प्रदान करते हुए कहा, ‘शत्रुघ्न! तुम अत्यंत वीर हो। लवणासुर का वध करके मधुपुर के धर्म की स्थापना करो। मैं तुम्हें भगवान विष्णु का एक अमोघ बाण देता हूं; उसी से विष्णु जी ने मधु और कैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। तुम इसी बाण से लवणासुर का वध करना। परंतु, ध्यान रहे कि जब तक शिव का त्रिशूल लवणासुर के पास है, उसे मारना असंभव है। अब उसे युद्ध के लिए तैल ललकारना है, जत उसके हाथ में त्रिशूल न हो।’ आज्ञा का पालन



दूत भेजा, किंतु लवणासुर उसे मारकर खा गया। तब स्वयं राजा मांधाता, विशाल सेना लेकर पहुंचे। परंतु, लवणासुर ने शिवजी का दिव्य त्रिशूल उठा लिया और उसके एक ही प्रहार से मांधाता तथा उनकी समस्त सेना को भस्म कर डाला।’ लवणासुर का यह वृत्तांत सुनकर शत्रुघ्न सावधान हो गए। वह मधुपुर के द्वार पर पहुंचकर उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। संयोग से उसी समय लवणासुर शिकार करके लौट

रहा था। उसके हाथ में शिवजी का त्रिशूल नहीं था। उसने द्वार पर खड़े शत्रुघ्न को देखकर उपहास करते हुए कहा, ‘मैं तेरे जैसे असंख्य योद्धाओं को मारकर खा चुका हूं। शत्रुघ्न ने निर्भीक उत्तर दिया, ‘मैं आज तेरे अत्याचारों का अंत करने आया हूं। लवणासुर हंस पड़ा और बोला, ‘रुक! मैं अपना दिव्य त्रिशूल लेकर आता हूं, फिर युद्ध होगा।’ इतना कहकर वह महल की ओर दौड़ा। शत्रुघ्न को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। उन्होंने श्रीराम द्वारा प्रदत्त अमोघ बाण धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह दिव्य बाण वज्र के समान वेग से उड़ता हुआ लवणासुर के वक्षस्थल में जा धंसा। बाण लगते ही लवणासुर धराशायी होकर गिर पड़ा। उसके वध के बाद वह दिव्य त्रिशूल भगवान शिव के पास लौट गया और तीनों लोक लवणासुर के आतंक से मुक्त हो गए।

मोदी को धमकाना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पड़ा भारी!

नीरज कुमार दुबे

कहने को तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शायद वह मोदी को अब तक अच्छे से जान ही नहीं पाए हैं। देखा जाये तो जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते नहीं, वह अक्सर धमकियों, प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव के सहारे उन्हें झुकाने का सपना देखते हैं। लेकिन मोदी का संकल्प साफ है कि भारत के हितों से समझौता नहीं होगा और देश को किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने नहीं देना है। उनके हर फैसले में यही दृढ़ता दिखाई देती है। दूसरी ओर, ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही भारत पर दबाव बनाने के लिए शुल्क, व्यापारिक दबाव और रूस से तेल खरीद बंद कराने जैसी तमाम कोशिशें कीं, लेकिन नई दिल्ली ने हर बार अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च रखा। अब अमेरिका एक बार फिर टैरिफ रूपी आर्थिक हथियार लेकर मैदान में उतरा है, लेकिन मोदी सरकार ने भी बिना देर किए वाशिंगटन को साफ संदेश दे दिया है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हित किसी विदेशी दबाव की कीमत पर तय नहीं होंगे।

हम आपको बता दें कि जिस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार अप्रैल 2025 में पेश किया गया था, वह करीब डेढ़ साल तक अमेरिकी राजनीति और ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताओं के बीच अटक रहा। लेकिन इस महीने यानि सितंबर 2026 में तत्वीर अचानक बदल गई। भारत में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनिपिंग के साथ सक्रिय कूटनीतिक भागीदारी के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस और ईरान पर अनेक प्रतिबंधों वाला विधेयक पारित कर दिया। घटनाक्रम का समय भले ही संयोग हो, लेकिन संदेश बेहद स्पष्ट है कि वाशिंगटन रूस से जुड़े देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अब शुल्क को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को तैयार है।



लेकिन भारत ने भी अमेरिका को उसी क्षण जवाब दे दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दो टुक कहा कि भारत अपने 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत बदलती बाजार परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा खरीदता रहेगा। इतना ही नहीं, नई दिल्ली ने अमेरिका को याद दिलाया कि इस कदम के भारत–अमेरिका संबंधों के साथ–साथ पूरे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में अमेरिकी पक्ष को पहले ही उच्च स्तर पर स्पष्ट रूप से बताया जा चुका है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। यानी अमेरिका शुल्क की धमकी दे सकता है, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा की कीमत पर किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल, जिस विधेयक को अब ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध अधिनियम 2026’ कहा जा रहा है, उसकी कहानी डेढ़ साल पुरानी है। अप्रैल 2025 में लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमफ़ेल्ड ने रूस के खिलाफ कड़े प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिबंधों की पहल की थी। इसके बाद लंबे समय तक इसे कांग्रेस और प्रशासन के बीच समर्थन जुटाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। जुलाई 2026 में प्लेइट हाउस से सहमति बनने के बाद इसकी राह खुली। अगस्त में सीनेट ने इसे 86 के मुकाबले 11 मतों से पारित किया और 16 सितंबर को प्रतिनिधि सभा ने 262 के मुकाबले 159 मतों से इसे मंजूरी दे दी। यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के तेल

और गैस के सबसे बड़े खरीदारों पर सी प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत और चीन इसके निशाने पर हैं। इसके पीछे अमेरिकी रणनीति रूस की ऊर्जा आय को चोट पहुंचाने की है, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए मास्को को मिलने वाले आर्थिक संसाधनों पर दबाव बनाया जा सके। विधेयक में रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के साथ–साथ प्रतिबंधों से बचने वाले उसके जहाजी बेड़े पर भी शिकंजा कसने का प्रावधान है। लेकिन अमेरिका शायद यह भूल रहा है कि भारत रूस से तेल किसी राजनीतिक एहसान के लिए नहीं खरीद रहा।

भारत की जरूरत है सस्ती, विश्वसनीय और लगातार उपलब्ध ऊर्जा। 2022 में रूस भारत के लिए कोई बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता नहीं था। रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप द्वारा रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए जाने से रूस का कच्चा तेल भारी छूट पर उपलब्ध हुआ और भारत ने अपने आर्थिक हित में इसे खरीदना शुरू किया। इसके बाद रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। वित्त वर्ष 2026 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी हिस्सेदारी 30.3 प्रतिशत रही और करीब 134.7 अरब डॉलर के कुल आयात में रूस से आने वाले तेल की कीमत 40.8 अरब डॉलर रही। जुलाई 2026 में तो भारत के आयातित तेल में रूसी हिस्सेदारी आधे से भी ज्यादा पहुंच गई।

इसके अलावा, आज वैश्विक परिस्थितियों को देखें तो वह भी सामान्य नहीं हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध और आपूर्ति संकट ने तेल बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाएं हैं और वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत भी दबाव में हैं। भारत 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन रूस और पश्चिम एशिया उसकी ऊर्जा सुरक्षा के मुख्य आधार बने हुए हैं। ऐसे समय में अचानक रूसी तेल बंद करना केवल रूस के खिलाफ फैसला नहीं होगा, बल्कि भारत की अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है।

यही कारण है कि पिछले साल अमेरिकी

दंडात्मक शुल्क भी भारत को रूसी तेल से पूरी तरह दूर नहीं कर सके। भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल की खरीद में बड़ी कटौती तब की जब रूस की प्रमुख तेल कंपनियों पर सीधे प्रतिबंध लगाए गए और व्यापार करना कठिन हो गया। लेकिन जैसे ही पश्चिम एशिया में आपूर्ति संकट गहराया, भारत ने फिर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। जुलाई में रूसी तेल की खरीद अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इससे एक बात साफ होती है कि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा कोई सौदेबाजी का विषय नहीं है।

यहां इस पूरे घटनाक्रम का सामरिक महत्व सामने आता है। अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है। जबकि रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। चीन भी रूसी ऊर्जा का बड़ा खरीदार है। साथ ही भारत एक साथ अमेरिका, रूस, चीन, ईरान तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने हितों का संतुलन साध रहा है। ऐसे में नई दिल्ली के सामने चुनौती किसी एक खेमे में जाने की नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बचाए रखने की है। इसके अलावा, ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी की पुतिन और जिनिपिंग के साथ बढ़ती कूटनीतिक निकटता ने जिस बदलती विश्व व्यवस्था की तत्वीर अमेरिका के सामने रखी, उसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी कांग्रेस का रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने वाला कदम कई सवाल खड़े करता है। सवाल उठता है कि क्या वाशिंगटन को यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि दुनिया अब उसकी शर्तों पर नहीं चलती? देखा जाये तो भारत, रूस और चीन का एक मंच पर आना और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था तथा संप्रभु समानता की वकालत करना उस अमेरिकी धर्मसंवादी सोच के लिए सीधी चुनौती है, जिसमें लंबे समय से आर्थिक ताकत को कूटनीतिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन बदलती दुनिया का संदेश साफ है। भारत सहित उभरती शक्तियां अब अपने राष्ट्रीय हितों का फैसला किसी बाहरी राजधानी के इशारे पर नहीं करेंगी।

आज का इतिहास

- 1905 नीदरलैंड के रोटटरडम शहर में विद्युत ट्रामलाइन की शुरुआत हुई।
- 1912 हॉलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ।
- 1922 हंगरी लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ।
- 1926 अमेरिका के मियामी में चक्रवाती तूफान से 250 लोगों की मौत।
- 1931 जापान की सेना ने पूर्वोत्तरी चीन में स्थित मन्चूरी के क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। यह कब्ज़ा चीन और जापान के बीच दूसरे युद्ध का कारण बना।
- 1947 अमेरिका में वायु सेना का गठन हुआ।
- 1947 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ।
- 1961 तत्कालीन सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया।
- 1967 नागालैंड ने अंग्रेज़ी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया।
- 1976 ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का जन्म हुआ। जिनका पूरा नाम रोनाल्डो रुइस नेज़ेरियो डेलीमा है।
- 1986 मुम्बई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान बम्बई से गुआ के बीच उड़ाया।
- 1987 अमरीका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने आज ही के दिन ये घोषणा की थी कि आने वाले कुछ सालों में 1000 परमाणु मिसाइलें ख़त्म कर दी जाएंगी।
- 1988 बर्मा ने अपना संविधान रद्द किया।
- 1986 मुम्बई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान उड़ाया।
- 1997 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ‘होलोग’ नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
- 1997 ओजोन परत की रक्षा के लिए 100 देशों ने सन् 2015 तक मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन बन्द करने का निश्चय किया।
- 1998 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का 1 अरब डॉलर दकाये की घोषणा।
- 2003 बका-अगरतला के बीच बस सेवा शुरू हुई।
- 2006 रूसी राकेट सोयूज़ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना।
- 2006 संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की दौड़ में अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व वित्तमंत्री अशरफ़ ग़नी शामिल।
- 2007 कनाडा में 1960 के दशक में जीवाश्म की खोज से तहलका मचाने वाले भारतीय जियोलॉजिस्ट जी. बी. मिश्रा को विशेष सम्मान से नवाजा गया।
- 2008 शोभना भरतीया एच. टी. मॉडिया की अध्यक्ष नियुक्त हुई।
- 2009 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कम्पनी एच. सी. एल. के संस्थापक अध्यक्ष शिव नायर को ब्रिटेन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

यूसीसी पर बिहार में बड़ा सवाल: भाजपा का एजेंडा चलेगा या सहयोगियों का मैथेमेटिक्स?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के ऐलान ने बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार इसलिए खास है क्योंकि यहां पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार है, लेकिन सरकार का राजनीतिक आधार सिर्फ भाजपा नहीं है।

जदयू, लोजपा (रामविलास), राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसे सहयोगी दल भी सत्ता के समीकरण का हिस्सा हैं। ऐसे में यूसीसी पर भाजपा का रुख और सहयोगियों की राजनीतिक जमीन आमने-सामने आती दिख रही है।

यूसीसी भाजपा के प्रमुख वैचारिक मुद्दों में रहा है। अमित शाह ने अब इसे 2029 से पहले एनडीए शासित राज्यों में लागू करने का लक्ष्य सामने रख दिया है। इसका सीधा अर्थ है कि बिहार में भी इस मुद्दे पर सरकार को आगे बढ़ना पड़ सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति में सवाल सिर्फ कानून बनाने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या गठबंधन के सभी पट्टक इसके लिए तैयार हैं?

यहीं से भाजपा के सामने चुनौती शुरू होती है। क्योंकि जिन दलों के साथ मिलकर सरकार चल रही है, उनके अपने सामाजिक आधार, राजनीतिक हित और मतदाता समूह हैं। यूसीसी जैसे संवेदनशील विषय पर वे भाजपा के राष्ट्रीय एजेंडे के साथ कितनी दूर तक चलेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

अमित शाह के बयान के बाद जदयू ने तत्काल हां कहने के बजाय सावधानी का रास्ता चुना। पार्टी ने कहा कि पहले कानून के प्रावधान सामने आने चाहिए और

उसके बाद उनका अध्ययन करके फैसला किया जाएगा। जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगर प्रावधान तार्किक होंगे तो पार्टी बिना वजह विरोध नहीं करेगी। साथ ही पार्टी के भीतर यह भी कहा गया है कि बिहार की सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।

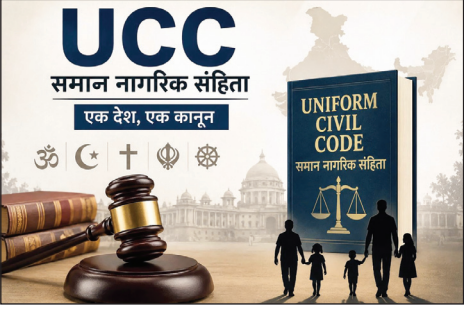
इस रुख को सीधे समर्थन या विरोध की श्रेणी में रखना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना साफ है कि भाजपा के ऐलान के बावजूद जदयू ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति बनाए रखी है। यही इस मुद्दे को महत्वपूर्ण बनाता है।

नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसले लेते रहे हैं। इसलिए यूसीसी पर उनकी पार्टी के लिए सवाल केवल वैचारिक नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक आधार को लेकर भी है।

लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने भी तत्काल समर्थन नहीं दिया। उन्होंने भारत के सामाजिक ताने-बाने की विविधता का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग-अलग वर्गों की अपनी नागरिक परंपराएं और रीति-रिवाज हैं। उन्होंने संविधान में कुछ समुदायों और क्षेत्रों के लिए मौजूद विशेष प्रावधानों का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि प्रस्ताव और उसके प्रावधान सामने आने के बाद पार्टी अपना रुख तय करेगी।

चिराग पासवान का यह रुख बताता है कि भाजपा के सहयोगी दल यूसीसी को सिर्फ भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के रूप में स्वीकार करने के बजाय उसके वास्तविक प्रावधानों को देखकर फैसला करना चाहते हैं।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उषेंद्र कुशवाहा का



रुख भी इसी तरह सावधानी वाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्यों की ओर से प्रस्ताव सामने आने के बाद ही उनकी पार्टी इस पर टिप्पणी करेगी। यानी कुशवाहा ने न तो अभी समर्थन की घोषणा की है और न ही विरोध का ऐलान किया है।

यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि कुशवाहा की पार्टी भी बिहार एनडीए का हिस्सा है। उनका बयान यह संकेत देता है कि सहयोगी दल अंतिम निर्णय से पहले यूसीसी के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, भाजपा ने लक्ष्य घोषित कर दिया है, लेकिन सहयोगियों ने अभी यह तय नहीं किया है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वे किस हद तक साथ चलेंगे।

इस बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी का रुख भी चर्चा का विषय है। हालिया रिपोर्टों में एचएएम को यूसीसी पर भाजपा के रुख के समर्थन में बताया गया है। लेकिन राजनीतिक रूप से दिलचस्प बात यह है कि मांझी की ओर से ऐसा कोई विस्तृत सार्वजनिक हस्तक्षेप सामने नहीं आया है, जैसा जदयू या चिराग की ओर से दिखाई दिया। इसलिए उनकी स्थिति

नरेन्द्र मोदी : सर्वांगीण विकास के प्रेरणादायक प्रतीक

दीपक कुमार त्यागी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में

आज विकास के पथ पर तेज़ी से अग्रसरित भारत, विकसित भारत बने के लिए सर्वांगीण विकास के कार्यों को धरातल पर मूर्त रूप देते हुए सफलता के नित-नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तेज़ी से आर्थिक सुधार हो रहे हैं, मोदी ने देश में परिवर्तन लाने के लिए शहर, कस्बों से लेकर के गांव, दुर्गम दूरदराज के इलाकों तक में भी अब विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के अनवरत विकास का कार्य युद्ध स्तर पर चलवाने का कार्य कर रहा है। 21वीं सदी की आधुनिकता की दौड़ में एआई व डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विज़न के दम पर स्वदेशी को तेज़ी से बढ़ावा देकर के भारत तेज़ी से आत्मनिर्भर बनने का मुकाम हासिल कर रहा है। देश में विश्वस्तरीय आधुनिक सड़क, सागर व नभ मार्ग विकास के नित-नए मार्ग खोल रहे हैं। देश के पास विश्वस्तरीय अत्याधुनिक हथियारों के जखीरे व सुविधाओं से सुसज्जित ट्रैंड सेना का पूरा बड़ा लावा लश्कर मौजूद है, जो दुश्मन देशों से घिरे होने के बाद भी देश की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का कार्य बखूबी करता है। वैश्विक स्तर पर कूटनीति और देश की विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत होती स्थिति के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आधुनिक भारत का शिल्पकार माना जाता है।

भारत में लंबे समय तक लगातार केंद्र की सत्ता में रहने का कीर्तिमान बनाते हुए एक लोकप्रिय जननेता के रूप में प्रधानमंत्री



नरेन्द्र मोदी अपनी राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने की कार्यशैली के दम पर आधुनिक, सशक्त, शक्तिशाली नए भारत के एक ऐसे सफल शिल्पकार बन चुके हैं, जिन्होंने आजादी के लगभग 7 दशकों का लंबा समय बीत जाने के बाद देश के दूरदराज, दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों तक में भी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का कार्य निरंतर शुरू कर रखा है, जो काबिले-तारीफ व अर्वांधित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनके कार्यकाल के दौरान देश में बड़े पैमाने पर धरातल पर नये भारत की परिकल्पना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का कार्य तेज़ी से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव तैयार करने का कार्य बखूबी कर रहा है। देश में आधुनिक रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, सड़क, रोपवे, एक्सप्रेस-वे, नेशनल हाईवे आदि जगह-जगह बन रहे हैं। पूरे देश में सड़क, हवाई, रेल व जल मार्ग से यात्रा व माल ढुलाई आदि की व्यवस्था को बहुत तेज़ी से विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की सीमाओं की रक्षा की बात करें तो आज देश के वीर योद्धाओं के हाथ दुश्मन पर कार्रवाई

को सिर्फ चुप्पी के आधार पर विरोध या समर्थन की किसी नई व्याख्या में बदलना उचित नहीं होगा।

फिलहाल उपलब्ध संकेत यही बताते हैं कि एचएएम भाजपा के पक्ष के ज्यादा करीब है, जबकि जदयू, चिराग और कुशवाहा ने प्रस्ताव देखने के बाद निर्णय लेने की बात कही है। यानी बिहार एनडीए के भीतर यूसीसी को लेकर तत्वीर एक जैसी नहीं है।

यहीं इस पूरे विवाद का राजनीतिक पक्ष सामने आता है। भाजपा के लिए यूसीसी एक घोषित वैचारिक मुद्दा है। लेकिन सहयोगी दलों के लिए हर बड़े फैसले का असर उनके अपने सामाजिक आधार पर भी पड़ता है।

जदयू को बिहार के व्यापक सामाजिक समीकरणों को देखना होगा। चिराग पासवान को अपने राजनीतिक आधार और सामाजिक विविधता के बीच संतुलन बनाना होगा। कुशवाहा की पार्टी को भी अपने प्रभाव वाले सामाजिक समूहों को ध्यान में रखना होगा। एचएएम के लिए परिस्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि उसका राजनीतिक रुख फिलहाल भाजपा के करीब दिखाई देता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि सहयोगी दल भाजपा के साथ हैं या नहीं। सवाल यह है कि वे भाजपा के यूसीसी एजेंडे के साथ कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं।

यूसीसी पर मतभेद सामने आने भर से बिहार सरकार के अस्तित्व पर तत्काल संकट मान लेना उचित नहीं होगा। गठबंधन सरकारों में कई मुद्दों पर सहयोगी दलों के अलग-अलग विचार होते हैं। असली परीक्षा तब होगी जब यूसीसी का ठोस मसौदा सामने आएगा और बिहार में उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

अगर मसौदे में ऐसे प्रावधान होते हैं जिन पर

के लिए पूरी आजादी के साथ खुले हुए हैं, जिसकी बानगी देश व दुनिया के लोग नकसल, आतंकियों, सर्जिकल स्ट्राइक व भारतवासियों के जीवन स्तर में सुधार करते हैं, मां भारती के वीर सपूत अब बिना किसी दबाव के आतंकवादियों व नक्सलियों के जहरीले फन को निरंतर कुचल कर के सफाया करने का कार्य बखूबी कर रहे हैं।

पिछले लगभग 4 या 5 दशक से आतंक की आग में झुलस रहे जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन को कायम करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अब वहां पर शांति है। धारा 370 को हटाकर के जम्मू-कश्मीर के निवासियों को दशकों से वंचित किए गए उनके हक को वापस दिया गया। वहीं देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जन धन योजना, कौशल भारत मिशन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्रमेव जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ह्रदय योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उजाला योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री ज्योति ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, सांवरन गोल्ड बॉन्ड योजना, उद्यम, स्टार्ट- अप इंडिया, सेतु भारतम योजना, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामोदय से भारत उद्यम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

सहयोगियों को आपत्ति नहीं होती, तो बातचीत के जरिए रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर सहयोगियों को लगे कि इससे उनके सामाजिक या राजनीतिक आधार पर सीधा असर पड़ेगा, तो असहमति ज्यादा गंभीर हो सकती है।

फिलहाल जदयू ने बातचीत का रास्ता चुना है और उसके नेता संजय झा के अमित शाह से चर्चा की संभावना है। इससे संकेत मिलता है कि एनडीए के भीतर संवाद की प्रक्रिया अभी बाकी है। बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के सामने यूसीसी इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि यह सरकार के शुरुआती दौर में ही भाजपा की वैचारिक प्राथमिकता और सहयोगियों की राजनीतिक जरूरतों के बीच संतुलन का सवाल लेकर आया है। एक तरफ अमित शाह का स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जदयू ने सावधानी बरती है, चिराग पासवान ने व्यापक चर्चा की बात कही है और उषेंद्र कुशवाहा ने प्रस्ताव सामने आने तक फैसला सुरक्षित रखा है। जीतनराम मांझी का पक्ष फिलहाल भाजपा के ज्यादा करीब बताया जा रहा है, लेकिन उनकी ओर से इस मुद्दे पर वैसी मुखरता नहीं दिखी है। बहरहाल, बिहार में यूसीसी की राह केवल विधानसभा की संख्या का गणित नहीं होगी। यह एनडीए के भीतर सहमति का गणित भी होगी।

और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है- बिहार में पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री वाली सरकार अपने सहयोगियों के सामाजिक आधार और भाजपा के वैचारिक एजेंडे के बीच कितना संतुलन बना पाती है? फैसला यूसीसी के मसौदे और उस पर होने वाली बातचीत से निकलेगा।

समझौता और संदेश : किशाऊ बांध

पर छह राज्यों में बनी सहमति

देवेश त्रिपाठी



विवाद बातचीत और सहमति से आगे बढ़ना इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि देश में नदी जल बंटवारे से जुड़े विवाद अक्सर विकास परियोजनाओं को वर्षों तक प्रभावित करते रहे हैं। हालांकि, इतनी बड़ी परियोजना की सफलता केवल राज्यों के बीच समझौते पर निर्भर नहीं करेगी। इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को भी उतनी ही गंभीरता से देखना होगा। परियोजना से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुल करीब 2,950 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने तथा हजारों लोगों के पुनर्वास की आशंका है। जाहिर है, जल संकट से निपटने के लिए बड़े जलाशयों और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जरूरत हो सकती है, पर विकास की कीमत प्रभावित समुदायों तथा पर्यावरण को अनदेखा करके नहीं चुकाई जा सकती। ऐसे में, प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजा, सम्मानजनक पुनर्वास और आजीविका की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करना परियोजना की स्वीकार्यता के लिए अहम होगा। राज्यों के बीच बनी यह सहमति देश के दूसरे हिस्सों में लॉबित नदी जल विवादों को सुलझाने की दिशा में यकीनन मिसाल हो सकती है, लेकिन यह स्थायी महत्व की उपलब्धि बने, इसके लिए परियोजना के सामाजिक व पर्यावरणीय दायित्वों को भी गंभीरता से लेना होगा।

सेवा से संकल्प तक : बदलते भारत की मोदी-यात्रा

डॉ. प्रवीण दाताराम गुपनामी

17 सितंबर की तिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मात्र नहीं था। यह उस राजनीतिक यात्रा को देखने का अवसर भी है, जिसने पिछले बारह वर्षों में भारत के शासन-विमर्श, विकास-दृष्टि और वैश्विक भूमिका को अनेक स्तरों पर प्रभावित किया है। 2014 में प्रारंभ हुई यह यात्रा अब उस पड़ाव पर है, जहाँ उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ-साथ उनके दीर्घकालीन प्रभावों का मूल्यांकन भी आवश्यक है।

मोदी सरकार के बारह वर्षों को किसी एक योजना, एक निर्णय या एक राजनीतिक नारे से नहीं समझा जा सकता। इसका व्यापक स्वरूप जनकल्याण, जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता, डिजिटल सशक्तीकरण, आधारभूत संरचना, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैश्विक सक्रियता के सम्मिलित प्रयास के रूप में दिखाई देता है। सबसे पहले शासन की उस शैली को देखना होगा, जिसने भारत के करोड़ों नागरिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया। जन-धन खाते, आधार और मोबाइल, इस छ्क्रू की त्रिमूर्ति ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को संरचना को बदला। मार्च 2026 तक जन-धन खातों की संख्या 57.71 करोड़ और आधार की संख्या 144 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। इसी डिजिटल आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और डिजिटल भुगतान का व्यापक विस्तार हुआ। मार्च 2026 में अकेले यूपीआई पर लगभग 2,264 करोड़ लेन-देन हुए, जिनका मूल्य 29.53 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। आज भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली देश की सीमाओं से बाहर भी पहुँच रही है।

उज्ज्वला से स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ भारत से शौचालय, जल जीवन मिशन से नल का जल, प्रधानमंत्री आवास से पक्का घर और आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा, इन योजनाओं ने करोड़ों परिवारों को लक्षित किया। सरकारी आकलनों के अनुसार 2014 के बाद शहरी कचरा प्रसंस्करण 16 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 82 प्रतिशत हुआ और डोर-टू-डोर कचरा संग्रह 43 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हुआ। राष्‍ट्र निर्माण कार्य को विचारवान नेतृत्व के साथ-साथ सड़क, रेल, बिजली, जल और संचार चाहिए। मोदी सरकार ने पूंजीगत व्यय को विकास की



केंद्रीय धुरी बनाया। इस धुरी का परिणाम रहा कि केंद्र का पूंजीगत व्यय 2014-15 के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया।

रेलवे में विद्युतीकरण विकास का प्रमुख उदाहरण है। मार्च 2026 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका था। वंदे भारत जैसी रेल सेवाओं ने आधुनिक भारतीय रेल की नई आकांक्षा को प्रतीकात्मक रूप भी दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में मार्च 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 532 बह्वु से अधिक हो चुकी थी, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 274.69 बह्वु तक पहुँच गई। सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के 2.82 बह्वु से बढ़कर 150.26 बह्वु हो गई है। नरेंद्र मोदी जी की प्रथम अवधारणा रही है - ‘ आत्मनिर्भर भारत’। इस ओर देखें तो हमें चित्र दिखता है कि भारत का रक्षा उत्पादन 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ रुपए हो गया। रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया और भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों तक पहुँच रहे हैं। ‘सक्षम भारत’ का यह सर्वाधिक ज्वलंत उदाहरण है।

इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी इसी दृष्टि का विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2026 में अपने संबोधन में पिछले बारह वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगभग सात गुना और मोबाइल फोन उत्पादन में 35 गुना वृद्धि का उल्लेख किया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का लागू होना भारतीय कर-व्यवस्था के इतिहास का बड़ा परिवर्तन था। अनेक अप्रत्यक्ष करों को एक साझा ढाँचे में लाने का यह प्रयास आर्थिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। जीएसटी की युक्तियुक्तकरण की यात्रा अभी जारी है।

मोदी काल को केवल आर्थिक और प्रशासनिक

परिवर्तनों से समझना अधूरा होगा। इस काल में सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय प्रतीकों को सार्वजनिक विमर्श में नई प्रमुखता मिली। अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्विकास, केदारनाथ सहित अनेक तीर्थस्थलों का विकास और भारत से बाहर गई पुरावस्तुओं की वापसी इसी व्यापक सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा है। यह सब औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के विमर्श का मूर्तिरूप स्वरूप है। 7 रसकोर्स से लोककल्याण का और राजपथ से कर्तव्य पथ का नामकरण एक बड़ा प्रतीक है।

2014 के बाद भारतीय विदेश नीति में सक्रियता और बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ी। 2023 की जी 20 अध्यक्षता इसका महत्वपूर्ण उदाहरण बनी। नई दिल्ली घोषणा पर सहमति और अफ्रीकी संध को जी 20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने की पहल ने भारत को ‘ग्लोबल साउथ’ के प्रश्नों को प्रमुखता से उठाने का अवसर दिया। चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को विश्व के सामने नए स्तर पर स्थापित किया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नया अध्याय खोला। अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमों के लिए खोलने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयासों ने विज्ञान को नई आर्थिक संभावनाओं से जोड़ने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।

किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का मूल्यांकन केवल उसके समर्थकों के उत्साह या विरोधियों की आलोचना से नहीं हो सकता। रोजगार की गुणवत्ता, कृषि की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता, सामाजिक समरसता, शहरी जीवन, छोटे उद्यमों की चुनौतियाँ और आर्थिक असमानता जैसे प्रश्न अभी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

मोदी सरकार की बारह वर्ष की यात्रा को समझने का सबसे उचित तरीका न तो केवल प्रशस्ति है और न केवल आलोचना। यह उस परिवर्तन को पहचानने का प्रयास है, जिसमें राज्य की क्षमता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को एक व्यापक राष्ट्रीय परियोजना से जोड़ने का प्रयास हुआ है।

मुफ्त यूपीआई की कीमत आखिर कौन चुकाएगा?

जयसिंह रावत

भारत में चाय के दस रुपये से लेकर मोबाइल फोन, रेल टिकट और हजारों रुपये की खरीदारी तक के लिए मोबाइल निकालकर क्यूआर कोड स्कैन करना इतना सहज हो चुका है कि शायद ही कोई सोचता हो कि स्क्रीन पर कुछ सेकंड में पूरा होने वाले इस भुगतान के पीछे बैंकों, सर्वरों, दूरसंचार नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणालियों का कितना विशाल ढांचा काम करता है। वर्षों तक इसका सीधा खर्च न ग्राहक ने महसूस किया, न दुकानदार ने। अब सरकार ने 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारी यूपीआई भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने का रास्ता खोलकर एक महत्वपूर्ण सवाल सामने रख दिया है- दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान व्यवस्थाओं में शामिल यूपीआई हमेशा मुफ्त कैसे रह सकती है और उसकी वास्तविक कीमत आखिर कौन चुकाए? सबसे पहले उस भ्रम को दूर करना जरूरी है जो नई व्यवस्था की खबर आते ही पैदा हुआ। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को यूपीआई से पैसा भेजना पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा, चाहे रकम 500 रुपये हो या 50 हजार। शुल्क केवल व्यक्ति से व्यापारी को किए गए निर्धारित भुगतान पर लागू होगा। व्यापारी को 2,000 रुपये तक का भुगतान भी एमडीआर से मुक्त रहेगा। छोटे व्यापारी, रेहड़ी-पट्टरी वाले और पड़ोस के वे दुकानें, जिन्हें यूपीआई क्यूआर के माध्यम से महीने में एक लाख रुपये तक मिलते हैं, भी शून्य एमडीआर के दायरे में रहेंगे। सरकार का कहना है कि इस कारण करीब 96 प्रतिशत व्यापारी यूपीआई लेन-देन नई व्यवस्था से प्रभावित नहीं होंगे। बदलाव मुख्यतः 2,000 रुपये से अधिक के पात्र व्यापारी भुगतान में होगा। इनमें 10,000 रुपये की खरीद पर 20 रुपये और अर्थात 5,000 रुपये पर 40 रुपये। 75 हजार रुपये या उससे अधिक के भुगतान में इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि सामग्री जैसे आवश्यक तथा कम मुनाफे वाले क्षेत्रों में

2,000 रुपये से ऊपर भी केवल पांच रुपये प्रति भुगतान की दर रखी गई है। पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान के लिए अलग कम दर निर्धारित की गई है। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू होगी है। एमडीआर कोई नया कर नहीं है और सरकार इसे अपने खजाने में नहीं लेती। यह डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले व्यापारी से लिया जाने वाला शुल्क है, जिसे भुगतान व्यवस्था से जुड़े बैंक और सेवा प्रदाता आपस में बांटते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में ऐसी व्यवस्था पहले से है। अंतर यह था कि जनवरी 2020 से यूपीआई व्यापारी भुगतान शून्य एमडीआर व्यवस्था में चल रहा था। इसी मुफ्त व्यवस्था ने यूपीआई को भारत के शहरों से गांवों और बड़े मॉल से फुटपाथ के ठेले तक पहुंचाने में असाधारण भूमिका निभाई। लेकिन मुफ्त का अर्थ यह नहीं कि व्यवस्था चलाने की कोई लागत नहीं है। यूपीआई के पीछे क्वॉन, क्लाउड भंडारण, बैंकिंग नेटवर्क, ग्राहक सहायता, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी पहचान और लगातार बढ़ते लेन-देन को संभालने की क्षमता चाहिए। उपलब्ध आंकलन के अनुसार भुगतान उद्योग को व्यक्ति-से-व्यापारी यूपीआई व्यवस्था चलाने पर सालाना करीब 20,700 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकार इसके लिए प्रोत्साहन देती रही है, लेकिन 2026-27 के बजट में इसके लिए एलएलए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। सवाल इसलिए स्वाभाविक है कि तेजी से बढ़ती प्रणाली की पूरी लागत अनिश्चितकाल तक सरकारी सहायता और सेवा प्रदाताओं पर छोड़ी जा सकती है या नहीं। यह चुनौती अब केवल बढ़ते लेन-देन को संभालने की भी नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में डिजिटल धोखाधड़ी के तरीके भी अधिक जटिल हो रहे हैं। भुगतान कंपनियों को साइबर सुरक्षा, संदिग्ध लेन-देन की पहचान और धोखाधड़ी रोकने वाली प्रणालियों को लगातार उन्नत करना पड़ रहा है। इसलिए यूपीआई को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने की बहस का एक पक्ष यह भी है कि पर्याप्त निवेश से सर्वर क्षमता और सुरक्षा मजबूत हो तथा भुगतान विफल होने या पैसा अटकने जैसी समस्याओं को कम करने की क्षमता बढ़े।

हॉकी प्लेयर गीता यादव का भव्य स्वागत

कबीरधाम। चीन में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली कवर्धा की बेटी गीता यादव के शहर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। ठाकुर देव चौक से भारत माता चौक तक निकली अभिनंदन रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डोल-नगाओं और भारत माता के जयकारों के बीच गीता का जगह-जगह फूल-मालाओं से स्वागत किया गया। गीता यादव के कवर्धा पहुंचने की खबर मिलते ही उनके माता-पिता, सर्व यादव समाज के पदाधिकारी, युवा और बड़ी संख्या में समाज के लोग स्वागत के लिए पहुंचे। ठाकुर देव चौक से गीता को रैली के साथ भारत माता चौक तक ले जाया गया। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर और

चीन में जिताया जूनियर महिला एशिया कप ट्रूर्नामेंट



आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। रैली में गीता के सम्मान में जमकर नारे लगाए गए।

साधारण किसान परिवार से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने तक गीता यादव का सफर क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों के

लिए प्रेरणादायक है।परिजनों और समाज के लोगों ने कहा कि गीता ने अपनी मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा के दम पर कवर्धा और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। भारत माता चौक पर आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में गीता को सम्मानित किया गया।इस दौरान उनके माता-पिता भी भावुक नजर आए। लोगों ने गीता के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता से क्षेत्र की बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी। जूनियर महिला एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान चीन को 1-0 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में गीता यादव ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

धमतरी के 7 गांवों में हाथियों को लेकर अलर्ट जारी

धमतरी। धमतरी के 7 गांवों में हाथियों के झुंड के पहुंचने से खलबली मच गई है। करेगांव वन परिक्षेत्र अधिकारी के मुताबिक चंदा हाथियों का झुंड एक बार फिर गांव के करीब पहुंच चुका है। गांव के बाहर हाथियों की मौजूदगी के चलते दहशत का माहौल है। फिलहाल हाथियों का झुंड जिसमें ज्यादातर दंतैल हाथी शामिल हैं, छुही बीट में डटे हुए हैं।

वन विभाग ने लोगों को जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है। वन विभाग के मुताबिक दंतैल हाथी वर्तमान में कक्ष क्रमांक क्र-143 के आसपास विचरण कर रहे हैं। हाथियों



का झुंड आगे बढ़कर जोगीडीह की आबादी क्षेत्र और धमतरी-करेगांव रेंज की ओर जाने की संभावना जताई जा रही है। जिसे देखते हुए जोगीडीह, छुही, पीपरछेड़ी, बाजारकूरीडीह, साल्हेभाट, सिरौदकला और कमारपारा को हार्ड अलर्ट पर रखा गया है। वहीं बासीखाई, झुरातराई और भालुचुवा गांवों में भी अलर्ट जारी किया गया है।

हाथियों की मौजूदगी को देखते

हुए वन विभाग की टीम लगातार इलाके की निगरानी कर रही है। पीपरछेड़ी और कमारपारा सहित प्रभावित क्षेत्रों में सुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क किया गया है। ग्रामीणों से कहा गया है कि हाथी की मौजूदगी के दौरान जंगल की तरफ न जाएं और किसी भी स्थिति में हाथी के करीब जाने या उसे परेशान करने की कोशिश न करें। वन विभाग ने यह भी अपील की है कि यदि किसी ग्रामीण को हाथी दिखाई देता है तो वह तत्काल नजदीकी वन कर्मचारी को इसकी सूचना दे, ताकि टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर सके।



65 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त, 500 किलो लहन नष्ट

पिथौरा। महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत चारभाटा में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 65 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके से करीब 500 किलो महुआ लहन भी बरामद हुआ, जिसे आबकारी टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि महुआ शराब बनाने के लिए केमिकल का भी उपयोग किया जाता था। आबकारी विभाग के अनुसार, आरोपी लंबे समय से अवैध शराब की भट्टी संचालित कर रहे थे। पिथौरा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

विश्वकर्मा पर एसईसीएल मानिकपुर खदान में उमड़ी भीड़

कोरबा। सृष्टि के पहले शिल्पकार और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती गुरुवार को कोरबा जिले में उत्साह और विधि-विधान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एसईसीएल की मानिकपुर ओपनकास्ट माईंस और सेंट्रल वर्कशॉप में विशेष और भव्य आयोजनों हुए। आम नागरिकों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस दिन खदान परिसर के भीतर प्रवेश की विशेष अनुमति मिलती है। जिससे उन्हें खदान की कार्यप्रणाली को करीब से देखने का दुर्लभ अवसर मिलता है। विश्वकर्मा जयंती पर सुबह से ही मानिकपुर खदान के साथ ही सेंट्रल वर्कशॉप में लोगों का तांता लगा हुआ था। अधिकारी और कर्मचारी सभी मिलकर विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करते हैं और भोग प्रसाद का वितरण करते हैं।

साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार

दुर्ग। साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे के वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले में साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े कुल 3,162 मूल बैंक खातों की पहचान की है। इनमें से 63 एफआईआर में 1,668 खातों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। इन प्रकरणों में अब तक 257 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

पुलिस के अनुसार, विभिन्न साइबर ठगी एवं ऑनलाइन सट्टा प्रकरणों से संबंधित कुल 2,75,50,091 रुपये की डिस्प्यूट राशि पर होल्ड लगाकर धनराशि के आगे हस्तांतरण और निकासी को रोकने की कार्रवाई की गई है।

दुर्ग पुलिस द्वारा 578 मूल बैंक खातों के संबंध में सत्यापन और इस्तगसा की कार्रवाई की गई है। संबंधित खाताधारकों और बैंकिंग जानकारी का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं 916 मूल बैंक खाते वर्तमान में लंबित हैं। इन खातों से संबंधित तकनीकी एवं वित्तीय विश्लेषण के आधार पर आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,

पुलिस ने की 3,162 मूल खातों की पहचान, 257 आरोपी गिरफ्तार



साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े मामलों में अपराधियों द्वारा अवैध धनराशि के लेन-देन और हस्तांतरण के लिए मूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे खातों की पहचान के लिए प्राप्त शिकायतों, बैंकिंग लेन-देन, केवायसी दस्तावेज, यूपीआई ट्रांजेक्शन और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों का लगातार विश्लेषण किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, साइबर अपराधियों और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े लोगों द्वारा कमीशन, आसान कमाई अथवा अन्य आर्थिक प्रलोभन देकर लोगों के बैंक खाते हासिल किए जाते हैं। इन खातों का

इस्तेमाल साइबर ठगी और अन्य अवैध गतिविधियों से प्राप्त धनराशि को जमा करने तथा विभिन्न बैंक खातों एवं डिजिटल माध्यमों के जरिए ट्रांसफर करने में किया जाता है। कुछ मामलों में खाताधारक अपना बैंक खाता दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध कराते हैं, जबकि कुछ मामलों में बैंकिंग लेन-देन का संचालन अन्य लोगों द्वारा किया जाता है। पुलिस बैंकिंग रिकॉर्ड, केवायसी दस्तावेज, यूपीआई ट्रांजेक्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर धनराशि के प्रवाह तथा संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। प्रकरणवार कार्रवाई के दौरान बैंक खातों

80 फीसदी राजस्व कोरबा से लेकिन सुविधा नहीं, केंद्र को 25 से ज्यादा पत्र लिखे लेकिन मांग नहीं सुनी गइ़: ज्योत्सना महंत

कोरबा। लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने गुरुवार को प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कोरबा सहित पूरे लोकसभा क्षेत्र से जुड़े रेल, भू-विस्थापन, रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा कि अपने प्रथम संसदीय कार्यकाल से लेकर वर्तमान कार्यकाल तक वे क्षेत्र की समस्याओं और विकास के मुद्दों को लगातार सदन और संबंधित विभागों के समक्ष उठाती रही हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। सांसद ने कहा कि ट्रेनों के विस्तार, टहराव और नई यात्री गाड़ियों के संचालन के मामले में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर शुरू करने के लिए उन्होंने जीएम, डीआरएम और रेल मंत्री तक लगातार पत्राचार



किया, लेकिन अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि रेलवे की प्राथमिकता क्या केवल कोयला परिवहन तक सीमित रह गई है? मंडल स्तरीय सांसदों की आगामी बैठक के लिए भी उन्होंने क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव भेजे हैं। सांसद ने एसईसीएल की परियोजनाओं से प्रभावित भू-विस्थापितों की समस्याओं को गंभीर

तक खानी पड़ी और प्रभावित परिवारों के मकानों को बलपूर्वक खाली कराया जा रहा है। वर्षों बाद जमीन अधिग्रहित किए जाने की स्थिति में किसानों को वर्तमान दर के अनुरूप मुआवजा मिलना चाहिए। सर्वसुविधायुक बसाहट उपलब्ध कराना भी जरूरी है। नियमानुसार बसाहट की व्यवस्था किए बिना प्रभावित परिवारों के

बताते हुए कहा कि हरदीबाजार, अमगांव, चुरैल, पाली, पड़निया सहित अनेक क्षेत्रों में ग्रामीणों की जमीन ली गई, लेकिन मुआवजा, नौकरी और बसाहट के मामले अब भी लंबित हैं।सांसद ने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले ग्रामीणों को कई बार लाठियों

मकान तोड़ने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एसईसीएल के मेडिकल अनफिट कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा भी सांसद ने उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मेडिकल बोर्ड की बैठक नहीं होने से कर्मचारियों के आश्रितों के सामने परेशानी खड़ी है। उन्होंने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए इस व्यवस्था को जल्द शुरू करने की मांग की। सांसद महंत ने कहा कि कोरबा के आसपास स्थित धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए वे लगातार प्रयास कर रही हैं। कनकी, चैतुरगढ़, कुदुरमाल, मड़वारानी, हनुमानगढ़ी, कोसगई और मातीन दाई सहित विभिन्न स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल की गई है। उनकी अनुशंसा पर विभिन्न निधियों से कई स्थानों पर विकास कार्य भी कराए गए हैं।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

बिलासपुर में महतारी वंदन योजना में 542 हितग्राही अपात्र

बिलासपुर। जिले में 542 हितग्राही महतारी वंदन योजना के तहत अपात्र पाए गए हैं। ये आंकड़े जिले में योजना का लाभ ले रहीं 4 लाख 17 हजार 902 महिलाओं की पात्रता जांच के दौरान सामने आए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपात्र हितग्राहियों से करीब 30 लाख रुपए की वसूली की है। अफसरों का कहना है कि वसूली और सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी है। महतारी वंदन योजना के तहत पात्र विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए की सहायता सिधे उनके आधार लिंक बैंक खातों में जमा की जाती है। बिलासपुर जिले में बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। शिकायतों के आधार पर विभाग ने हितग्राहियों की पात्रता का सत्यापन शुरू किया। जांच के दौरान 542 महिलाएं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं मिलीं। बिलासपुर जिले में महतारी वंदन योजना की अब तक 31 किश्तों में करीब 12.16 अरब रुपए हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा किए गए हैं। जांच के दौरान ऐसे मामले भी सामने आए हैं।

पतीले नदी के किनारे भोलेनाथ के साथ विराजे हैं देव शिल्पी भगवान

एमसीबी। 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के नगर पंचायत जनकपुर क्षेत्र में पतीले नदी के किनारे देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा और भगवान भोलेनाथ की प्राचीन प्रतिमाएं आस्था का केंद्र हैं। नदी की कल-कल धारा, चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण के बीच भोलेनाथ के साथ विराजे हैं विश्वकर्मा भगवान। जानिए मान्यता और पर्यटन के साथ ही इस स्थल के महत्व चकदही के इस देवस्थल से स्थानीय लोगों की गहरी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्षेत्रवासियों के अनुसार, यहां भगवान विश्वकर्मा और शंकर भगवान की पूजा-अर्चना पीढ़ियों से होती आ रही है। बुजुर्गों के समय से चली आ रही इस परंपरा को आज भी लोग श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं। स्थानीय परिवारों के लिए यह स्थल केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक विरासत और आस्था का हिस्सा है। स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से भगवान विश्वकर्मा और भोलेनाथ की आराधना करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

करियर कंसल्टेंसी संचालक पति पत्नी सहित 3 गिरफ्तार

दुर्ग। भिलाई की स्मृति नगर पुलिस ने विदेश में एमबीए की पढ़ाई और नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला सहित 3 को गिरफ्तार किया है। सुमित अरमरकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराया कि टॉप करियर कंसल्टेंसी के संचालक गगन गुप्ता, उसकी पत्नी स्वाती अग्रवाल गुप्ता और पार्टनर जसवंदर सिंह डिंगवा ने विदेश में स्क्रूम प्रवेश और पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था। आरोपियों ने सुमित को यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की अलग-अलग यूनिवर्सिटियों में एमबीए में एडमिशन दिलाने की बात कही। इसके साथ ही विदेश में नौकरी लगवाने का आश्वासन भी दिया। इसके लिए रुपये खर्च होने की बात कही। आरोपियों के बताए बैंक खातों में प्रार्थी ने अलग-अलग किस्तों और चेक के जरिए कुल 19 लाख रुपए ट्रांसफर किए। रुपये लेने के बाद भी करियर कंसल्टेंसी के संचालक लगातार सुमित को विदेश भेजने का आश्वासन देते रहे।

दुर्ग सेंट्रल जेल में रेड, कई प्रतिबंधित चीजें बरामद

दुर्ग। अक्सर ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि जेल में कैदी मोबाइल फोन रखते हैं और बाहर लोगों को धमकाते हैं। जेल प्रबंधन और पुलिस लगातार इन शिकायतों पर कार्रवाई भी करती रहती है। गुरुवार को एक बार फिर जिला एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक दबिश देकर पूरे जेल परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई कार्रवाई से जेल प्रशासन और बंदियों में हड़कंप मच गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अगुवाई में करीब 100 अधिकारियों और जवानों की टीम ने जेल को घेरकर बिना पूर्व सूचना के जांच शुरू की। तलाशी के लिए 10 अलग-अलग टीमों बनाई गई थी। टीमों ने एक-एक बैरक, शौचालय, अहाता और संभावित छिपने वाले स्थानों की बारीकी से जांच की। करीब दो घंटे चली कार्रवाई में दो मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बीटी, सिगरेट, तंबाकू, चिलम, लाइटर, कैंची और नेलकटर समेत कई प्रतिबंधित सामान बरामद किए गए। सभी बैरकों की हमने जांच की है।

भालू भयंकर से हुआ सामना, वन विभाग की टीम ने किया अलर्ट

धमतरी। इसान और वन्यजीवों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को उदती-सीतानटी टाइगर रिजर्व एरिया में भालू के हमले में 2 ग्रामीण बुरी तरह से जखमी हो गए। एक ग्रामीण की हालत गंभीर है, जिसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक सुबह के वक्त कुछ गांव वाले अरसीकन्हार रेंज के अर्जुनी जंगल में लकड़ी बीनने गए थे। तभी सामने से भालूओं का झुंड आ गया। ग्रामीणों ने बताया कि झुंड में कुल चार भालू थे। ग्रामीणों ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन 2 लोग भालू के हमले में जखमी होने से खुद को नहीं बचा पाए। गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण का इलाज जिला अस्पताल धमतरी में किया जा रहा है। गांव वालों ने बताया कि जब भालू ने हमला किया तो सभी लोग अगल-अलग दिशा में भागे। लेकिन हमलावर भालूओं की संख्या भी चार थी लिहाज दो लोग भालू के हमले में जखमी हो गए। घायलों को सिर और चेहरे पर जखम आए हैं।

बुजुर्गों के बीच पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव

लोरमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और जनसेवा के सफल 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लोरमी के मानस मंच पर ‘स्नेह, सेवा एवं सम्मान समारोह’ का भव्य आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में आयोजित ‘सेवा संकल्प’ अभियान का यह कार्यक्रम बेहद भावुक और यादगार पल का साक्षी बना। समारोह के दौरान जब उपमुख्यमंत्री अरुण साव मंच से उतरकर क्षेत्र के वरिष्ठ पेंशनधारियों और निराश्रित बुजुर्गों के पास पहुंचे और एक-एक कर उनके चरण पखारे तो पूरा माहौल



भावुक हो उठा। साव ने बड़े ही आत्मीय भाव से बुजुर्गों के सामने शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लिया। अपने बेटे और जनसेवक को इस तरह चरणों में झुके देख कई बुजुर्गों की आंखें छलक आईं और उन्होंने साव के सिर पर हाथ रखकर दिल खोलकर दुआएं दीं।

भारतीय संस्कृति और अपनों के प्रति अनन्य आदर का यह सजीव दृश्य पूरे लोरमी क्षेत्र के दिलों को छू गया। कार्यक्रम में लोरमी और आसपास के ग्रामीण अंचलों से पहुंचे 2000 से अधिक बुजुर्गों का साव ने आत्मीयता से स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर

क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ तथा हवन-यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। अपने परिवारतुल्य क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, लोरमी मेरा घर है और आप सभी मेरे अपने हैं। हमारे बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं, जिसके जीवन का अनुभव और सीख हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपनों का सम्मान करना हमारी माटी के संस्कार हैं। आप सभी का यह स्नेह और आशीर्वाद ही मुझे दिन-रात जनता की सेवा करने की शक्ति देता है।

सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों से भारी काम

तखतपुर। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत भारी के शासकीय प्राथमिक शाला तेलियापुरान, संकुल केंद्र भारी से एक मामला सामने आया है। यहां छोटे बच्चों से पानी से भरी भारी बाल्टी उठवाया गया, जिसका वीडियो भी आया है। वीडियो आने के बाद स्कूल में बच्चों की सुरक्षा और उनसे इस तरह का काम कराए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल के छोटे बच्चों से शौचालय में पानी भरकर ले जाने का काम कराया जा रहा था। सामने आई जानकारी के अनुसार, जिस बाल्टी में बच्चे पानी भरकर ले जा रहे थे, उसकी क्षमता करीब 15 से 20 लीटर बताई जा रही है। इतनी मात्रा में पानी छोटे बच्चों के लिए उठकर ले जाना मुश्किल नजर आ रहा है। मामले से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो में बच्चे पानी से भरी बाल्टी को उठाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। बाल्टी का वजन अधिक होने के कारण बच्चे उसे उठाने के बजाय



नाजुक हाथों से उठवाई गई पानी से भरी बाल्टी, वीडियो सामने आने के बाद उठे सवाल

जमीन पर रखकर खींचते हुए आगे ले जाते दिखाई दे रहे हैं। जब बच्चों से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि सर ने बाथरूम का दरवाजा खोलकर पानी भरकर आने और दरवाजा बंद कर देने के लिए कहा है। बच्चों के अनुसार, उन्हें इसी तरह पानी भरकर

ले जाने के लिए कहा गया था।मामला सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले छोटे बच्चों से इतनी भारी बाल्टी में पानी उठवाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या स्कूल में पानी या सफाई व्यवस्था के लिए कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है? यदि बच्चों से इस तरह का काम कराया जा रहा है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कम उम्र के होते हैं। भारी वजन उठाने के दौरान उनके हाथ, पैर, कमर या शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगने की आशंका भी रहती है। इसके अलावा पानी से भरी बाल्टी को जमीन पर खींचकर ले जाने के दौरान बच्चे के फिसलने का खतरा भी हो सकता है। मामला सामने आने के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों के बीच भी चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि स्कूल बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षित वातावरण के लिए होता है।

नक्सलमुक्त होने के साथ चमकता नया बस्तर

छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1 अप्रैल 2026 की सुबह एक नई उम्मीद और स्थायी शांति का पैगाम लेकर आई। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नक्सलवाद के खत्मे के लिए तय की गई 31 मार्च की ऐतिहासिक डेडलाइन समाप्त हो गई, और इसी के साथ बस्तर समेत देश के नक्सल प्रभावित अंचलों में दशकों पुराने 'लाल आतंक' के सूर्यास्त की आधिकारिक इबारत लिख दी गई।

शांति स्थापना की त्रि-स्तरीय रणनीति

बस्तर में शांति स्थापना की प्रक्रिया कोई संयोग नहीं, बल्कि एक बेहद सोची-समझी और योजनाबद्ध 'त्रि-स्तरीय रणनीति' का परिणाम है। सुरक्षा बलों के कैंपों ने इसमें एक नींव (धुरी) की तरह काम किया है।

सुरक्षा कैंप को भरना (योजनाबद्ध विस्तार)

पहले बस्तर के कई इलाके 'नो-गो ज़ोन' थे, जहां नक्सलियों का समानांतर शासन चलता था।

रणनीतिक स्थान चयन: सुरक्षा बलों ने 'पिसर मूवमेंट' के तहत नक्सलियों के गढ़ के चारों ओर कैंप स्थापित किए। बीते दो वर्षों में जो 108 नए कैंप बने, वे रैंडम नहीं थे। उन्हें उन रास्तों पर बनाया गया जहां से नक्सली रसद और सूचनाएं प्राप्त करते थे। फरवर्ड पोस्ट (एफओबी) इन कैंपों को नक्सलियों के 'कोर एरिया' (जैसे अबुझमाड़, पुवर्ती, सिलगेर) के भीतर स्थापित किया गया। इससे नक्सलियों की आवाजाही प्रतिबंधित हो गई और वे रक्षात्मक मुद्रा में आ गए।

कैंप बना 'विकास का प्रवेश द्वार'

बस्तर में एक प्रसिद्ध कहावत बन गई है 'जहां कैंप पहुंचा, वहां सड़क पहुंची। सड़क सुरक्षा: कैंपों का सबसे पहला काम उन सड़कों के निर्माण को सुरक्षा देना था जो दशकों से अधूरी थीं। कैंपों के बीच की दूरी कम होने से ठेकेदारों और मजदूरों में डर खत्म हुआ। **लॉजिस्टिक्स हब:** कैंप केवल जवानों के रहने की जगह नहीं रहे। वे निर्माण सामग्री (सीमेंट, डामर) के भंडारण केंद्र बन गए। कैंपों की सुरक्षा में ही पुल-पुलियों का निर्माण संभव हुआ, जिससे बारिश में भी अंदरूनी इलाके कटे नहीं रहे।

बस्तर में अब विकास के विश्वास के साथ शांति का सूर्योदय हो चुका है। लेकिन करीब 36 साल तक लाल आतंक की आग में झूलसे बस्तर में बदलाव एवं विकास की बयार बह रही है। **पढ़िए बस्तर में नक्सलवाद के अंत की योजनाओं और रणनीति की पूरी कहानी के साथ विकसित बस्तर के परिकल्पना...**



स्थानीय लोगों में विश्वास का जागना

विश्वास तब जागता है जब डर खत्म होता है और लाभ सामने दिखता है।

संवाद और सहायता

कैंपों में तैनात जवानों (विशेषकर बस्तर फाइटर्स, जिनमें स्थानीय युवक शामिल हैं) ने ग्रामीणों से उनकी गोंडी और हलबी भाषा में बात की। कैंपों में चलने वाले 'सिविल एक्शन प्रोग्राम' के तहत मुफ्त इलाज और दवाइयों ने ग्रामीणों की धारणा बदली।

आर्थिक बदलाव

सड़कों के आने से आदिवासियों के वनोपज (इमली, महुआ, टोरा) को सीधे बाजार तक पहुंच मिली। बिचौलियों का अंत हुआ और ग्रामीणों की आय बढ़ी। जब ग्रामीणों ने देखा कि कैंप आने से उनका जीवन आसान हो रहा है, तो उन्होंने नक्सलियों के 'कैंप विरोधी' प्रोपेगेंडा को नकारना शुरू कर दिया।

लोकतंत्र की वापसी

कैंपों की सुरक्षा के कारण ही अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान केंद्र बन सके और लोगों ने निडर होकर वोट दिया। इतना ही नहीं आजादी के इतने सालों बाद वहां तिरंगा लहराया।

3 | आर्थिक सशक्तिकरण और उद्योग

बस्तर में 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना ताकि स्थानीय युवाओं को वहीं रोजगार मिले। सहकारी समितियों के माध्यम से इमली और महुआ जैसे लघु वनोपजों का सही दाम दिलाना।

4 | शिक्षा और खेल

उच्च शिक्षा के लिए नए कॉलेज और देश का सबसे आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना। खिलाड़ियों को 2036 के ओलिंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार करना।

5 | पर्यटन का नया हब

नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर को 'एडवेंचर टूरिज्म' का केंद्र बनाना। कांव के पुल, कैनोपी वॉक और होम-स्टे जैसी योजनाएं शुरू करना।

लाल आतंक के खिलाफ जंग के महत्वपूर्ण तथ्य

बस्तर फाइटर्स: आतंक और हिंसा के खिलाफ जंग

नक्सलवाद की कमर तोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका 'बस्तर फाइटर्स' की रही है। यह छत्तीसगढ़ पुलिस की एक विशेष इकाई है जिसमें केवल स्थानीय आदिवासियों को भर्ती किया गया है। इसमें कई ऐसे जवान शामिल हैं जो कभी खुद नक्सली थे या जिनके परिवार को नक्सलियों ने प्रताड़ित किया था। उन्हें जंगल की रग-रग का पता है, जिससे नक्सलियों का 'होम ग्राउंड एडवांटेज' खत्म हो गया।

'पुवर्ती': नक्सलियों के अजेय किले का ढहना

बीजापुर जिले का 'पुवर्ती' गांव, जो दुर्दांत नक्सली कमांडर हिड़मा का पैतृक गांव है, वहां दशकों तक किसी सुरक्षा बल के जवान ने कदम नहीं रखा था। फरवरी 2024 में वहां सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में, इस गांव में अब पक्की सड़क, बिजली और एक स्कूल है। हिड़मा के गांव में तिरंगा फहराना नक्सलियों के लिए सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक हार साबित हुई।

'लाल गलियारा' अब 'ईको-टूरिज्म हब'

जो इलाके कभी 'लैंडमाइन' के लिए बदनाम थे, उन्हें अब सरकार पर्यटन के लिए खोल रही है। चित्रकोट और तीरथगढ़ से आगे, अब पर्यटन विभाग उन अंदरूनी इलाकों में 'होम-स्टे' योजना शुरू कर रहा है, जो कभी नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप हुआ करते थे। अबुझमाड़ के कुछ हिस्सों को 'बर्ड वाचिंग' और 'एडवेंचर ट्रेकिंग' के लिए विकसित किया जा रहा है।

नक्सलियों का 'दैक्स तंत्र' ध्वस्त

नक्सली मुख्य रूप से तेंदूपत्ता व्यापारियों, लौह अयस्क परिवहन और बुनियादी ढांचा ठेकेदारों से 'लेवी' (अवैध वसूली) वसूलते थे। सरकार ने बैंकिंग सखियों और डिजिटल पेमेंट को अंदरूनी गांवों तक पहुंचा दिया है। अब तेंदूपत्ता का भुगतान सीधे ग्रामीणों के बैंक खातों में होता है, जिससे नक्सलियों की करोड़ों रुपये की अवैध वसूली का जरिया बंद हो गया है।

विकास का एजेंडा

बस्तर में सरकार की योजनाएं तेजी से पहुंचाई जा रही हैं। इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है।

'बस्तर ओलंपिक': बंदूकों की जगह खेल



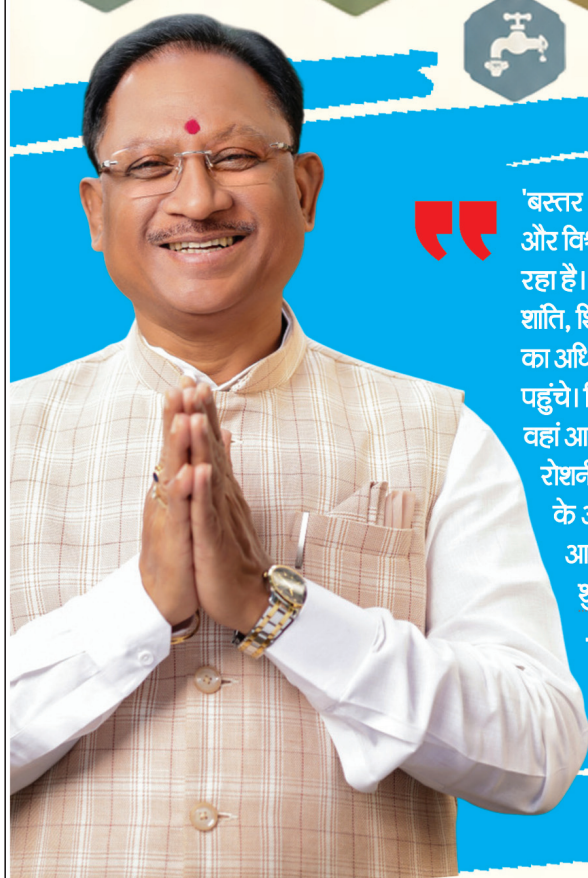
2024-25 में आयोजित 'बस्तर ओलंपिक' एक क्रांतिकारी कदम रहा। इसमें अंदरूनी गांवों के उन युवाओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें नक्सली अपने संगठन में भर्ती करने का प्रयास कर रहे थे। खेल के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिली और कई खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरियों में खेल कोटे से भर्ती किया जा रहा है।

भाषा का सेतु: 'गोंडी और हलबी' में संवाद

सुरक्षा बलों ने महसूस किया कि नक्सलियों की ताकत उनकी भाषा और स्थानीय संवाद था। सुरक्षा कैंपों में तैनात अधिकारियों को स्थानीय गोंडी और हलबी भाषा सिखाई जाती है। जब जवान ग्रामीणों से उनकी मातृभाषा में बात करते हैं, तो 'अजनबीपन' खत्म होता है और लोग नक्सलियों की सूचनाएं खुद सुरक्षा बलों को देने लगे हैं।

'पोटा केबिन' का सफल मॉडल

बस्तर में शिक्षा के लिए 'पोटा केबिन' (पोर्टेबल और न टूटने वाले आवासीय स्कूल) एक मिसाल बन गए हैं। नक्सलियों ने जिन स्कूलों को बम से उड़ा दिया था, वहां अब इन केबिन स्कूलों में हजारों आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं।



1 | कनेक्टिविटी और बैंकिंग

हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना। किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा और पोस्ट ऑफिस की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

2 | बुनियादी सुविधाएं

हर घर को बिजली, स्वच्छ पेयजल (नल से जल), गैस सिलेंडर और शौचालय। आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और हर गांव के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जाल।



विश्वकर्मा जयंती पर राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने श्रमिक हित में की तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं

श्रमवीरों के परिश्रम और पसीने से हो रहा समृद्ध छग का निर्माण: साय

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हजारों श्रमिकों के साथ मुख्यमंत्री ने प्रज्वलित किया ‘आशीर्वाद का दीया’



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के श्रमवीर अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और पसीने से समृद्ध एवं विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की नई इबारत लिख रहे हैं। गांवों के खेत-खलिहानों से लेकर शहरों की ऊंची इमारतों तक, सड़कों और पुलों से लेकर सिंचाई परियोजनाओं, उद्योगों और अधोसंरचना के निर्माण तक प्रदेश की प्रगति की हर तस्वीर में हमारे श्रमिक भाई-बहनों की मेहनत समाहित है। छत्तीसगढ़ ने अपने गठन के 25 वर्षों में विकास के जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उनके पीछे हमारे मेहनतकश हाथों का बड़ा योगदान है। यही हाथ आने वाले वर्षों में विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को भी साकार करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेशभर से आए हजारों श्रमिक भाई-बहनों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और भगवान विश्वकर्मा से छत्तीसगढ़ की सुख, शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के आराध्य हैं। वे हमें श्रम के सम्मान और अपने हुनर पर गर्व करने की प्रेरणा देते हैं।

शहरों में बनेंगे सर्वसुविधायुक्त आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू होगी ई-बाइक सहायता योजना



मुख्यमंत्री श्री साय ने महासम्मेलन में राज्य की नवीन उपकर कटौती वेबसाइट का शुभारंभ किया तथा पीवीसी एवं क्यूआर कोड युक्त नवीन श्रमिक पंजीयन कार्ड का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का उपयोग केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि श्रमिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ पंजीयन से लेकर योजनाओं का लाभ पहुंचाने तक की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड व्यवस्था से रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों को बड़ी सुविधा मिली है। अब श्रमिक देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करते हुए भी राशन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह पीएफ व्यवस्था में तकनीकी सुधारों से रोजगार या कार्यस्थल बदलने पर भी श्रमिकों के लिए खाते से जुड़ी सुविधाओं की निरंतरता आसान हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि श्रमिकों तक पहुंचाई गई है। उन्होंने प्रदेश के सभी पात्र श्रमिकों से श्रम विभाग में अपना पंजीयन कराने और योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।

1.43 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में 51.32 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि अंतरित



श्रमिक बहनों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री ने किया भोजन

राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन के दौरान आत्मीयता से भरा दृश्य उस समय देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आई श्रमिक बहनों के साथ बैठकर दोपहर के भोजन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भोजन के दौरान श्रमिक बहनों से सहजता से बातचीत की। उन्होंने उनके कामकाज, परिवार और बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने यह भी पूछा कि उन्हें श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई तो नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी है, जब उनका लाभ पात्र श्रमिक तक सरलता और समय पर पहुंचे। उन्होंने श्रमिक बहनों से संवाद के दौरान उनके अनुभव भी जाने। मुख्यमंत्री को अपने बीच बैठकर सहजता से भोजन करते और परिवार के सदस्य की तरह बातचीत करते देखकर श्रमिक बहनों में विशेष उत्साह दिखाई दिया।

श्रमिक परिवारों से मजबूत होगा छग: बृजमोहन



सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती और प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए लोगों से अपने घर, आंगन और मोहल्लों में आशीर्वाद का दीयाज प्रज्वलित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने और महिलाओं को ई-रिक्शा के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने जैसी पहल श्रमिक परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में रोजगार मेले का आयोजन कर लगभग तीन हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री सुनील सोनी, विधायक श्री पुनन्दर मिश्रा, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल, विभिन्न निगम-मंडलों के अध्यक्ष, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमांशुखर गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बड़ी संख्या में श्रमिक भाई-बहन उपस्थित थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थायी समिति की बैठक संपन्न



रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर स्थित कार्यालय में आज राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थायी समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। 32वें अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन के तहत आयोजित इस बैठक में विभिन्न राज्यों के निर्वाचन आयुक्तों ने स्थानीय निकाय चुनावों को और अधिक सुगम, निष्पक्ष, आधुनिक तकनीक से लैस एवं समय पर कराने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में स्थायी समिति द्वारा बनाई गई तीन उप-समितियों के कामकाज की प्रगति पर चर्चा की गई। इसमें राज्यों में लागू तकनीकी पहलों और ऑनलाइन व्यवस्थाओं के बेहतर बना सकें। इसी तरह जरूरत पड़ने पर राज्यों के बीच ईवीएम साझा करने के लिए एक ईवीएम प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर तैयार करने पर विमर्श हुआ, जिसकी जिम्मेदारी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग संभाल रहा है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना पर हुई खुली बहस के बाद अब खदान और कोल माइंस का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इसी मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। बघेल ने कहा कि जिस तरह रायपुर प्रेस क्लब में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ पीएम आवास पर आमने-सामने बहस हुई, उसी तरह मुख्यमंत्री साय भी मीडिया के सामने आकर खदान के मुद्दे पर चर्चा करें। बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री के पास खनन विभाग भी है। ऐसे में खदानों और खनन से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है, यह खुली बहस में सामने आ सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रेस क्लब में आमने-सामने बैठकर चर्चा करने की चुनौती दी। भूपेश बघेल के इस चैलेंज पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार की तरफ से जो भी तथ्य हैं, वे जनता के सामने आ रहे हैं। यानी बघेल जहां खदान के मुद्दे पर आमने-सामने बहस चाहते हैं, वहीं मुख्यमंत्री साय ने सरकार की ओर से तथ्यों के जनता के सामने आने की बात कही है।

भाजपा को बड़ा झटका, इस नगर पंचायत के 8 पार्षदों ने छोड़ी पार्टी सदस्यता



रायगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन रायगढ़ जिला के पुरीसर ब्लॉक में चल रहे भाजपा के सेवा, संकल्प अभियान को बड़ा झटका लगा है। पुरीसर नगर पंचायत के 8 पार्षदों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को सार्वजनिक हस्ताक्षरित त्याग पत्र सौंप है। इस घटनाक्रम से पार्टी में खलबली मची हुई है। रायगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष अरुणधर दीवान को त्याग पत्र सौंपने वाले पुरीसर नगर पंचायत के पार्षदों में वार्ड 6 पार्षद बलराम, वार्ड 14 पार्षद शौकीलाल चौहान, वार्ड-11 पार्षद रुपेश कुमार साव, वार्ड 1 पार्षद प्रदीप यादव, वार्ड 2 पार्षद फारुलाल प्रधान, वार्ड-3 पार्षद मंजू पटेल, वार्ड 7 पार्षद वरुण महणा और नगर पंचायत उपाध्यक्ष उमेश साव शामिल हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

हॉकी एशिया कप में प्रदेश की गीता-मधु का दमदार प्रदर्शन



रायपुर। चीन के मोको शहर में आयोजित जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में छत्तीसगढ़ की गीता यादव और मधु सिसदार ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। बिलासपुर के राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की आवासीय हॉकी अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दोनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में प्रभावी खेल दिखाते हुए चार-चार गोल दागे। उनके इस प्रदर्शन से बिलासपुर आवासीय हॉकी अकादमी के साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम के मुकाबलों के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने लगातार अपनी छाप छोड़ी। दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबले में मधु सिसदार ने एक गोल कर भारत की जीत में योगदान दिया। इसके बाद मलेशिया के खिलाफ भारत ने 11-1 से शानदार जीत दर्ज की, जिसमें गीता यादव ने दो गोल दागे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भी छत्तीसगढ़ की दोनों बेटियों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा।

बस्तर के बड़े अलनार में रोपे गए 300 पौधे



रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को बस्तर जिले के ग्राम बड़े अलनार में एक वृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अंचलों में हरियाली के विस्तार के उद्देश्य से कुल 300 फलदार एवं छायादार पौधे रोपे गए। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, जनपद अध्यक्ष श्री संतोष बघेल, जिला पंचायत सदस्य श्री निदेश दीवान, जनपद सदस्य श्री गौरव कश्यप, जनपद पंचायत सदस्य श्री रायधर दीवान तथा स्थानीय सरपंच श्रीमती मंगली बाई, जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्वेता वर्मा उपस्थित रहीं। पौधरोपण के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

चक्रधर समारोह में ओ.पी. ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह



रायपुर। 41वें चक्रधर समारोह, रायगढ़-2026 के अंतर्गत आयोजित अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय पुरुष-महिला कुश्ती प्रतियोगिता में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी शामिल हुए। मोती महल परिसर में आयोजित कुश्ती के रोमांचक मुकाबलों ने उपस्थित दर्शकों को उत्साह और उमंग से भर दिया। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनके खेल कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया।

सेवा संकल्प अभियान के तहत गौरेला में विशेष रक्तदान शिविर



रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल गौरेला के ब्लड बैंक में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा। विशेष रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपन्की, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री समीरा पैकरा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., नगर पालिका परिषद गौरेला के अध्यक्ष श्री मुकेश दुबे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

लोकभवन में मनाया गया विश्वकर्मा जयंती



रायपुर। लोकभवन में आज विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से मनाई गई। राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी ने भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश-प्रदेश के खुशहाली के लिए कामना की। उन्होंने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्रीमती सत्यनामा दुबे एवं लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

खेल संघों के साथ समन्वय से खिलाड़ियों को मिलेंगे ज्यादा मंच, खेल गतिविधियों में तेजी के निर्देश

प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बढ़ेंगे अवसर

रायपुर। प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के लिए अधिक से अधिक अवसर और मंच तैयार करने खेल एवं युवा कल्याण विभाग खेल संघों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय पर जोर दे रहा है। खेल गतिविधियों को जिला स्तर तक विस्तार देने के साथ खेल प्रतिभाओं की खोज और उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में खेल विभाग और खेल संघ कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्री आकांक्षा शिक्षा खलखो ने आज राज्य के खेल संघों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर गतिविधियों में तेजी लाने और आपसी समन्वय मजबूत करने के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर स्थित खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालनालय में आयोजित बैठक में प्रदेश के 25 से अधिक प्रमुख राज्य खेल संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक श्री प्रभाकर पाण्डेय, उप संचालक (वित्त) श्री रवि अग्रवाल, सहायक संचालक श्री रुस्सम सारंग और खेल अधिकारी श्री गिरीश शुक्ला भी बैठक में मौजूद थे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो ने सभी खेल संघों को अपना वार्षिक खेल कैलेंडर अनिवार्य रूप से खेल संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों की पूर्ण नियोजित जानकारी उपलब्ध होने से विभाग और संघ मिलकर प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण तथा खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी 33 जिलों में जिला स्तरीय खेल संघों के चरणबद्ध पंजीयन और विभागीय मान्यता की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने पर भी विशेष जोर दिया। बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग के साथ दूरस्थ अनुसूचित क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को व्यापक स्तर पर पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। सुश्री खलखो ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को अवसर केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों से निकलने वाली प्रतिभाओं को भी प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के पर्याप्त मंच मिलें। इसके लिए जिला स्तर पर खेल संघों की सक्रिय भूमिका अहम है।

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के अथक जनसेवा और समर्पण काल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को बलौदाबाजार जिले में सेवा संकल्प अभियान का ऐतिहासिक शुभारंभ हुआ। इस खास अवसर पर आयोजित आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जिले भर में एक साथ लगभग 11 लाख दीपक जलाकर जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त किया गया। जिला मुख्यालय स्थित चौपाटी में आयोजित मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर इस महाअभियान की विधिवत शुरुआत की। दीप प्रज्वलन के मुख्य कार्यक्रम से पहले राजस्व मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने शहीद वीर नारायण सिंह चौक पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया। इसके पश्चात ढोल-नगाड़ों की गूंज और भारी जनउत्साह के साथ चौक से चौपाटी तक एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का सबसे प्रमुख और मनमोहक केंद्र बिंदु विवेकानंद सरोवर बना, जहां सवा लाख दीयों की स्पर्धिम रौशनी और वृक्षों पर सजी रंग-बिरंगी लाइटों ने पूरे वातावरण को दिव्य और अलौकिक स्वरूप प्रदान कर दिया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHMHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/11/10, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.